



भारत का राजपत्र The Gazette of India

सी.जी.-जी.जे.-अ.-17092026-276304
CG-GJ-E-17092026-276304

असाधारण
EXTRAORDINARY

भाग III—खण्ड 4
PART III—Section 4

प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 553]

नई दिल्ली, बृहस्पतिवार, सितम्बर 10, 2026/ भाद्र 19, 1948

No. 553]

NEW DELHI, THURSDAY, SEPTEMBER 10, 2026/ BHADRA 19, 1948

अंतरराष्ट्रीय वित्तीय सेवा केंद्र प्राधिकरण

अधिसूचना

गांधीनगर, 8 सितंबर, 2026

अंतरराष्ट्रीय सेवा केंद्र प्राधिकरण (इलेक्ट्रॉनिक ट्रेडिंग प्लेटफॉर्म) विनियम, 2026

फा.सं. आईएफएससीए/जीएन/2026/016.— अंतरराष्ट्रीय सेवा केंद्र प्राधिकरण अधिनियम, 2019 (2019 का 50) की धारा 12 की उप-धारा (1) और धारा 13 की उप-धारा (1) के साथ पठित धारा 28 की उप-धारा (1); भारतीय रिजर्व बैंक अधिनियम, 1934 (1934 का 2) की धारा 45ब के अधीन प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, अंतरराष्ट्रीय सेवा केंद्र प्राधिकरण निम्नांकित नियम बनाता है, अर्थातः

अध्याय ।

प्रस्तावना

1. संक्षिप्त शीर्षक और आरंभ

- (1) इन नियमों को अंतरराष्ट्रीय सेवा केंद्र प्राधिकरण (इलेक्ट्रॉनिक ट्रेडिंग प्लेटफॉर्म) विनियम, 2026 कहा जाएगा।
- (2) ये नियम शासकीय राजपत्र में इनके प्रकाशित होने की तारीख से प्रवृत्त होंगे।

2. परिभाषाएं

(1) इन नियमों में, जब तक संदर्भ में कुछ और न कहा गया हो, यहां परिभाषित शब्दों का वही तात्पर्य होगा जो नीचे दिया गया है, और उनसे जुड़े शब्दों का तात्पर्य भी उसी के अनुसार समझा जाएगा, -

- (क) "अधिनियम" का तात्पर्य अंतरराष्ट्रीय सेवा केंद्र प्राधिकरण अधिनियम, 2019 (2019 का 50) से है;
- (ख) "एल्गोरिथमिक ट्रेडिंग प्रणाली (एटीएस)" का तात्पर्य हार्डवेयर, सॉफ्टवेयर, प्रक्रियाओं और उन विधियों से है जिनका उपयोग प्रणाली-संचालित निष्पादन तंत्र का उपयोग करके इलेक्ट्रॉनिक ट्रेडिंग प्लेटफॉर्म पर लेनदेन आरंभ करने के लिए किया जाता है;
- (ग) "प्राधिकरण" का तात्पर्य अधिनियम की धारा 4 की उप-धारा (1) के अधीन स्थापित अंतरराष्ट्रीय सेवा केंद्र प्राधिकरण से है;
- (घ) 'सक्षम प्राधिकरण' का तात्पर्य है:
 - (i) अध्यक्ष; या
 - (ii) अध्यक्ष द्वारा यथा-निर्धारित पूर्णकालिक सदस्य या पूर्णकालिक सदस्यों की समिति या प्राधिकरण का/के अधिकारी।
- (ङ) "योग्य लिखत" का तात्पर्य भारतीय रिजर्व बैंक अधिनियम, 1934 में परिभाषित प्रतिभूतियों, पैसा बाजार लिखतों, विदेशी मुद्रा और व्युत्पन्न, या प्राधिकरण द्वारा समय-समय पर यथा-निर्दिष्ट अन्य लिखतों से है।
स्पष्टीकरण: संदेह को दूर करने के लिए, स्पष्ट किया जाता है कि इस परिभाषा के दायरे में इस खंड में बताई गई वे लिखतें भी शामिल होंगी जो भारतीय रुपये में निर्धारित की गई हैं लेकिन जिनका निपटान किसी विनिर्दिष्ट विदेशी मुद्रा में किया जाता है।
- (च) "योग्य क्षेत्राधिकार" का तात्पर्य पहली अनुसूची में विनिर्दिष्ट क्षेत्राधिकारों से है;
- (छ) "इलेक्ट्रॉनिक ट्रेडिंग प्लेटफॉर्म" का तात्पर्य अंतरराष्ट्रीय वित्तीय सेवा केंद्र में स्थित इलेक्ट्रॉनिक प्रणाली से है, जिसके माध्यम से भागीदार नियमित रूप से एक या अधिक योग्य लिखतों के विक्रय, क्रय या विनिमय की पेशकश देते हैं और जो, ऐसी पेशकश को स्वीकार किए जाने पर, प्रतिभागियों के मध्य ऐसी योग्य लिखतों का इलेक्ट्रॉनिक प्रणाली के माध्यम से या किसी अन्य तरीके से समाशोधन और निपटान सक्षम बना सकता है;
- (ज) "इलेक्ट्रॉनिक ट्रेडिंग प्लेटफॉर्म ऑपरेटर (इलेक्ट्रॉनिक ट्रेडिंग प्लेटफॉर्म ऑपरेटर)" का तात्पर्य विनियम 5 के उप-विनियम (2) के अधीन इलेक्ट्रॉनिक ट्रेडिंग प्लेटफॉर्म के संचालन के लिए रजिस्ट्रीकरण प्रदान किया गया है;
- (झ) "अंतरराष्ट्रीय वित्तीय सेवा केंद्र (अंतरराष्ट्रीय वित्तीय सेवा केंद्र)" का वही तात्पर्य होगा जो अधिनियम की धारा 3 की उप-धारा (1) के खंड (छ) के अंतर्गत इसे दिया गया है;
- (ञ) "मुख्य प्रबंधकीय कार्मिक का वही तात्पर्य होगा जो कंपनी अधिनियम, 2013 (2013 का 18) की धारा 2 के खंड (51) में इसे दिया गया है;

- (ट) इन विनियमों के प्रयोजनार्थ "बाजार दुरुपयोग" का तात्पर्य इलेक्ट्रॉनिक ट्रेडिंग प्लेटफ़ॉर्म पर किसी प्रतिभागी द्वारा मैन्युअल रूप से या एल्गोरिथ्मिक ट्रेडिंग प्रणाली के माध्यम से अन्य प्रतिभागी(यों) को अनुचित रूप से हानि पहुँचाने, इलेक्ट्रॉनिक ट्रेडिंग प्लेटफ़ॉर्म पर मूल्य तंत्र को विकृत करना, या योग्य लिखितों के लिए बनावटी आपूर्ति और मांग उत्पन्न करने के उद्देश्य से इलेक्ट्रॉनिक ट्रेडिंग प्लेटफ़ॉर्म पर की गई कार्रवाई से है;
- (ठ) इन विनियमों के प्रयोजनार्थ "निवल मूल्य" का तात्पर्य प्रदत्त इक्विटी पूंजी, अनिवार्य रूप से परिवर्तनीय अधिमान शेयर, मुक्त रिज़र्व, शेयर प्रीमियम खाता में शेष और परिसंपत्ति की बिक्री से होने वाले अधिशेष को दर्शाने वाले पूंजीगत रिज़र्व से है, लेकिन इसमें संचित हानि शेष, अमूर्त परिसंपत्तियों का बही-खाता मूल्य और आस्थगित राजस्व व्यय, यदि कोई हो, के लिए समायोजित परिसंपत्ति के पुनर्मूल्यांकन द्वारा सृजित रिज़र्व शामिल नहीं होंगे;
- स्पष्टीकरण: संदेह दूर करने के लिए, स्पष्ट किया जाता है कि अनिवार्य रूप से परिवर्तनीय, संचयी या असंचयी अधिमान शेयर, जो अनिवार्य रूप से इक्विटी शेयरों में परिवर्तनीय है, और शेयरधारक समझौता(तों) में ऐसी अधिमान पूंजी को किसी भी समय आहरित करने पर स्पष्ट रूप से निषेध होना चाहिए।
- (ड) "प्रतिभागी" का तात्पर्य इलेक्ट्रॉनिक ट्रेडिंग प्लेटफ़ॉर्म के माध्यम से योग्य लिखित में लेन-देन करने वाले व्यक्ति से है;

(2) इन नियमों में प्रयोग किए गए और परिभाषित न किए गए शब्द और वाक्यांश, लेकिन जो भारतीय रिज़र्व बैंक अधिनियम, 1934 (1934 का 2), बैंकिंग विनियम अधिनियम, 1949 (1949 का 10), या कंपनी अधिनियम, 2013 (2013 का 18) या उनके अधीन बनाए गए किसी नियम या विनियम में परिभाषित हैं, उनका वही तात्पर्य होगा जो उस अधिनियमों, नियमों या विनियमों के अधीन बनाए गए या उनमें किए गए किसी सांविधिक परिवर्तन या पुनः अधिनियमन, जैसा भी मामला हो, में निर्धारित किया गया है।

अध्याय II

रजिस्ट्रीकरण

3. रजिस्ट्रीकरण के लिए आवेदन

- (1) कोई भी व्यक्ति अंतरराष्ट्रीय वित्तीय सेवा केंद्र में इलेक्ट्रॉनिक ट्रेडिंग प्लेटफ़ॉर्म तब तक संचालित नहीं कर सकता जब तक उसने इन विनियमों के अधीन इलेक्ट्रॉनिक ट्रेडिंग प्लेटफ़ॉर्म ऑपरेटर के रूप में रजिस्ट्रीकरण प्राप्त न किया हो:

बशर्ते कि अंतरराष्ट्रीय वित्तीय सेवा केंद्र की बैंक इकाई को रजिस्ट्रीकरण कराने की आवश्यकता नहीं होगी यदि ऐसी इकाई या इसका मूल बैंक, जैसा भी मामला हो:

- क) अपने इलेक्ट्रॉनिक ट्रेडिंग प्लेटफ़ॉर्म पर योग्य लिखतों में खरीद अथवा बिक्री भावों का एक मात्र प्रदाता हो; और
- ख) ऐसे इलेक्ट्रॉनिक ट्रेडिंग प्लेटफ़ॉर्म के माध्यम से किए गए प्रत्येक लेनदेन का प्रतिपक्ष हो।

बशर्ते यह भी कि, यदि कोई व्यक्ति अंतरराष्ट्रीय वित्तीय सेवा केंद्र के बाहर इलेक्ट्रॉनिक ट्रेडिंग प्लेटफ़ॉर्म संचालित करता है और अंतरराष्ट्रीय वित्तीय सेवा केंद्र में विद्यमान किसी एंटीटी को सेवाएँ देता है, तो उसे इन विनियमों के अधीन इलेक्ट्रॉनिक ट्रेडिंग प्लेटफ़ॉर्म ऑपरेटर के रूप में रजिस्ट्रीकरण कराने की आवश्यकता नहीं होगी।

- (2) अंतरराष्ट्रीय वित्तीय सेवा केंद्र में निगमित कंपनी इलेक्ट्रॉनिक ट्रेडिंग प्लेटफॉर्म ऑपरेटर के रूप में कार्य करने के लिए रजिस्ट्रीकरण कराने की पात्र होगी:

बशर्ते कि योग्य क्षेत्राधिकार में इलेक्ट्रॉनिक ट्रेडिंग प्लेटफॉर्म संचालित करने वाली एंटीटी (चाहे किसी भी नाम से जानी जाए) अंतरराष्ट्रीय वित्तीय सेवा केंद्र में शाखा स्थापित कर सकती है और इन विनियमों के अधीन ऐसा रजिस्ट्रीकरण करा सकती है।

बशर्ते यह भी कि, अंतरराष्ट्रीय वित्तीय सेवा केंद्र में स्थापित कोई वित्तीय संस्थान भी प्राधिकरण द्वारा यथा-निर्धारित सेवा-शर्तों के अधीन रजिस्ट्रीकरण प्रमाणपत्र पाने का पात्र हो सकता है।

- (3) इलेक्ट्रॉनिक ट्रेडिंग प्लेटफॉर्म ऑपरेटर के रूप में कार्य करने के लिए रजिस्ट्रीकरण का आवेदन प्राधिकरण द्वारा यथा-निर्दिष्ट शुल्क सहित निर्धारित प्ररूप और तरीके से प्राधिकरण को प्रस्तुत किया जाएगा।

4. रजिस्ट्रीकरण प्रदान करने की आवश्यक शर्तें

- (1) विनियम 3 के अधीन फ़ाइल किए गए आवेदन की जाँच करते समय, प्राधिकरण रजिस्ट्रीकरण देने के आवश्यक कारकों पर विचार करेगी, जिनमें निम्नलिखित शामिल हैं:

- (क) आवेदक या उसके प्रवर्तक(कों) का ट्रैक रिकॉर्ड, प्रबंधन की विशेषज्ञता और वित्तीय सुदृढता;
- (ख) पर्याप्त व्यावसायिक और अन्य संबंधित अनुभव रखने वाले वैयक्तिकों को नियुक्त करने की क्षमता;
- (ग) द्वितीय अनुसूची में यथा-निर्दिष्ट "उपयुक्त एवं समुचित" मानदंडों पर खरा उतरने वाले निदेशक, मुख्य प्रबंधकीय कार्मिक और आवेदक के नियंत्रणकर्ता अर्थात् वे वास्तविक व्यक्ति जो अंततः आवेदक के कामकाज, परिसंपत्तियों या कार्यनीतिक निर्णयकर्ता, नियंत्रक, या प्रभावित करने वाले हैं;

स्पष्टीकरण: संदेह को दूर करने के लिए, यह स्पष्ट किया जाता है कि रजिस्ट्रीकरण प्रमाणपत्र माँगने यह सुनिश्चित करेगा कि ऐसे व्यक्ति रजिस्ट्रीकरण की वैधता के दौरान हर समय "उपयुक्त एवं समुचित" बने रहें।

- (घ) जोखिम प्रबंधन प्रणाली और उनसे संबंधित आंतरिक नियंत्रण की सुदृढता;
- (ङ) इन विनियमों में निर्दिष्ट निवल मूल्य की आवश्यकता को पूरा करने की योग्यता;
- (च) आवेदक द्वारा प्रस्तुत की गई कारोबार योजना और अनुमानों की व्यवहार्यता।

5. रजिस्ट्रीकरण प्रदान करना

- (1) रजिस्ट्रीकरण के लिए आवेदन पर विचार करने के बाद, यदि प्राधिकरण संतुष्ट है कि आवेदक, प्रथम दृष्टया, रजिस्ट्रीकरण प्रदान किए जाने की शर्तों को पूरा करता है, तो प्राधिकरण रजिस्ट्रीकरण प्रदान करने से पूर्व आवेदक द्वारा पूरी की जाने वाली अतिरिक्त शर्तों सहित या इनके बिना "सैद्धांतिक अनुमोदन" जारी कर सकता है:

बशर्ते कि आवेदक को दिया गया "सैद्धांतिक अनुमोदन" प्राधिकरण द्वारा रद्द किया जा सकता है यदि आवेदक "सैद्धांतिक अनुमोदन" में विनिर्दिष्ट शर्तों को प्राधिकरण की संतुष्टि के अनुसार पूरा करने में असमर्थ रहता है।

(2) प्राधिकरण यह सुनिश्चित होने पर कि आवेदक ने "सैद्धांतिक अनुमोदन" प्रदान करते समय लगाई गई अन्य शर्तों, यदि कोई हों, सहित इन विनियमों में विनिर्दिष्ट आवश्यकताओं को पूरा कर लिया है, इलेक्ट्रॉनिक ट्रेडिंग प्लेटफॉर्म ऑपरेटर के रूप में कार्य करने के लिए उचित समझी गई और नीचे दी गई शर्तों के अधीन रजिस्ट्रीकरण प्रदान करता है:

(क) वे योग्य लिखतें जिनकी इलेक्ट्रॉनिक ट्रेडिंग प्लेटफॉर्म पर विक्रय, क्रय या विनिमय के लिए पेशकश की जा सकती है;

(ख) ऐसे प्लेटफॉर्म के भागीदार बनने के पात्र व्यक्तियों की श्रेणियां।

(3) उप-विनियम (2) में विनिर्दिष्ट शर्तों के अलावा, इलेक्ट्रॉनिक ट्रेडिंग प्लेटफॉर्म ऑपरेटर को प्राधिकरण द्वारा समय-समय यथा-निर्दिष्ट अतिरिक्त शर्तों का भी पालन करना होगा।

(4) उप-विनियम (2) के अधीन दिया गया रजिस्ट्रीकरण तब तक वैध रहेगा जब तक कि उसे प्राधिकरण रद्द न कर दे या इलेक्ट्रॉनिक ट्रेडिंग प्लेटफॉर्म ऑपरेटर उसे अभ्यर्पित न कर दे:

6. रजिस्ट्रीकरण से इनकार

(1) आवेदन की जांच के बाद, यदि प्राधिकरण इस राय पर पहुँचता है कि रजिस्ट्रीकरण प्रमाणपत्र प्रदान नहीं किया जा सकता, तो वह आवेदक को कमियों के बारे में सूचित करेगा और उन्हें ठीक करने के लिए तीस दिन का समय देगा:

बशर्ते कि प्राधिकरण, अपने विवेकानुसार, तीस दिन की इस अवधि को, जितना वह उचित समझे, और भी बढ़ा सकता है।

बशर्ते यह भी कि, अध्यक्ष की अनुमति के बिना इस अवधि को नब्बे दिन से अधिक नहीं बढ़ाया जाएगा; अध्यक्ष लिखित कारणों के साथ इस अवधि को एक सौ अस्सी दिनों तक बढ़ा सकते हैं।

(2) यदि आवेदक निर्धारित समय के भीतर प्राधिकरण की संतुष्टि के अनुसार ऐसी कमियों को ठीक करने में विफल रहता है, तो प्राधिकरण रजिस्ट्रीकरण देने से इनकार कर देगा और इसके कारणों सहित आवेदक को इसकी सूचना देगा:

बशर्ते कि लिखित अनुरोध फ़ाइल करके अपनी बात रखने का उचित अवसर दिए बिना ऐसा कोई इनकार नहीं किया जाएगा।

(3) जिस आवेदक के आवेदन को उप-विनियम (2) के अधीन अस्वीकार कर दिया गया है, वह प्राधिकरण द्वारा इनकार किए जाने की सूचना देने की तारीख से छह (6) माह की अवधि के बाद रजिस्ट्रीकरण के लिए नया आवेदन प्रस्तुत कर सकता है।

7. रजिस्ट्रीकरण का निलंबन या निरस्तीकरण

यदि प्राधिकरण इस बात से संतुष्ट है कि कोई इलेक्ट्रॉनिक ट्रेडिंग प्लेटफॉर्म ऑपरेटर अपने रजिस्ट्रीकरण प्रमाणपत्र की शर्तों, इन विनियम के उपबंधों, प्राधिकरण द्वारा जारी आदेश या निदेश का पालन करने में विफल रहा है, या इलेक्ट्रॉनिक ट्रेडिंग प्लेटफॉर्म ऑपरेटर की गतिविधियाँ प्रतिभागियों के हितों के विरुद्ध हैं, तो वह ऐसे इलेक्ट्रॉनिक ट्रेडिंग प्लेटफॉर्म ऑपरेटर को प्रदान किए गए रजिस्ट्रीकरण को निलंबित या निरस्त कर सकता है:

बशर्ते कि लिखित अनुरोध फ़ाइल करके अपनी बात रखने का उचित अवसर दिए बिना ऐसे इलेक्ट्रॉनिक ट्रेडिंग प्लेटफॉर्म ऑपरेटर के रजिस्ट्रीकरण को निलंबित या निरस्त करने का कोई आदेश जारी नहीं किया जाएगा।

8. रजिस्ट्रीकरण का अभ्यर्पण

- (1) कोई इलेक्ट्रॉनिक ट्रेडिंग प्लेटफॉर्म ऑपरेटर प्राधिकरण के पास अपने रजिस्ट्रीकरण को अभ्यर्पित करने के लिए यथा-निर्दिष्ट प्ररूप और विधि से आवेदन फ़ाइल कर सकता है।
- (2) उप-विनियम (1) के अधीन फ़ाइल किए गए आवेदन की जांच करने और इस बात से संतुष्ट होने पर कि रजिस्ट्रीकरण अभ्यर्पित करने से अंतरराष्ट्रीय वित्तीय सेवा केंद्र में वित्तीय सेवा बाज़ार या भागीदारों के हितों पर कोई विशेष विपरीत प्रभाव नहीं पड़ेगा, प्राधिकरण यथोचित शर्तों के अधीन अभ्यर्पण की अनुमति दे सकता है।
- (3) रजिस्ट्रीकरण का अभ्यर्पण प्राधिकरण द्वारा स्वीकार किए जाने पर ही प्रभावी होगा।

9. निवल मूल्य अपेक्षाएं

- (1) अंतरराष्ट्रीय वित्तीय सेवा केंद्र में कंपनी के रूप में इलेक्ट्रॉनिक ट्रेडिंग प्लेटफॉर्म ऑपरेटर का निवल मूल्य हर समय कम से कम यूएसडी 200,000 या किसी निर्धारित विदेशी मुद्रा में इस राशि के समकक्ष होना चाहिए।
- (2) शाखा के रूप में स्थापित इलेक्ट्रॉनिक ट्रेडिंग प्लेटफॉर्म ऑपरेटर को, अपनी मूल कंपनी के साथ हर समय कम से कम यूएसडी 200,000 या किसी निर्धारित विदेशी मुद्रा में इसके समकक्ष निवल मूल्य बनाए रखना होगा।
- (3) जोखिम प्रबंधन के उपाय के रूप में, प्राधिकरण किसी भी समय इलेक्ट्रॉनिक ट्रेडिंग प्लेटफॉर्म ऑपरेटर के ट्रेडिंग के स्वरूप और पैमाने को ध्यान में रखते हुए अधिक निवल मूल्य की आवश्यकता निर्धारित कर सकता है।
- (4) इलेक्ट्रॉनिक ट्रेडिंग प्लेटफॉर्म ऑपरेटर को हर वित्तीय वर्ष के समाप्त होने के छह माह के भीतर प्राधिकरण को लेखापरीक्षित निवल मूल्य प्रमाणपत्र प्रस्तुत करना होगा।
- (5) आवश्यक निवल मूल्य में कतिपय कमी होने पर, इलेक्ट्रॉनिक ट्रेडिंग प्लेटफॉर्म ऑपरेटर को तुरंत पूरा करना होगा और ऐसा होने के पंद्रह दिनों के भीतर सक्षम प्राधिकारी को इसके अनुपालन की रिपोर्ट देनी होगी।

अध्याय III**परिचालन दिशानिदेश****10. सामान्य दायित्व**

इलेक्ट्रॉनिक ट्रेडिंग प्लेटफॉर्म ऑपरेटर को निम्नांकित कार्य करने होंगे:

- (क) इलेक्ट्रॉनिक ट्रेडिंग प्लेटफॉर्म पर निष्पक्ष और व्यवस्थित ट्रेडिंग सुनिश्चित करने के लिए पारदर्शी नियम और प्रक्रियाएँ बनाना और उन्हें बनाए रखना;
- (ख) आदेशों के व्यवस्थित और कुशलतापूर्वक निष्पादन के लिए प्रयोजन मानदंड निर्धारित करना और आवश्यक अवसंरचना तैयार करना;
- (ग) इलेक्ट्रॉनिक ट्रेडिंग प्लेटफॉर्म के तकनीकी कामकाज के सही प्रबंधन के लिए प्रणालीगत बाधाओं के जोखिम से निपटने के लिए प्रभावी ट्रेडिंग निरंतरता व्यवस्था करने सहित ठोस प्रबंधन करना और उसका अनुरक्षण करना;
- (घ) इलेक्ट्रॉनिक ट्रेडिंग प्लेटफॉर्म पर ट्रेड किए जा सकने वाली योग्य लिखतों को निर्धारित करने के मानदंडों के बारे में पारदर्शी नियम बनाना और उनका अनुरक्षण करना;

- (ड) प्रतिभागियों को सुविचारित निवेश का निर्णय लेने में सक्षम बनाने के लिए प्रतिभागियों के स्वरूप और ट्रेड योग्य लिखितों के प्रकार को ध्यान में रखते हुए, पर्याप्त उपलब्ध सार्वजनिक जानकारी तक पहुँच प्रदान करना;
- (च) हितों के टकराव की पहचान करके, उसे कम करने, उसका खुलासा करने और उसकी निगरानी के उपायों सहित टकराव के प्रबंधन के लिए व्यापक ढाँचा बनाना और उसका अनुरक्षण करना; इसमें अन्य बातों के साथ-साथ ऐसी स्थितियाँ भी शामिल होंगी जहाँ इलेक्ट्रॉनिक ट्रेडिंग प्लेटफॉर्म ऑपरेटर या उससे जुड़ी कंपनियाँ प्रत्यक्ष या परोक्ष रूप से प्रतिभागियों के रूप में भाग लें;
- (छ) इलेक्ट्रॉनिक ट्रेडिंग प्लेटफॉर्म पर ट्रेड को निष्पादित या प्रस्तुत करने के लिए प्रतिभागियों को स्क्रीन-आधारित ट्रेडिंग प्रणाली उपलब्ध कराना;
- (ज) बाज़ार की अखंडता सुनिश्चित करने के लिए मूल्य, मात्रा और निगरानी के लिए वास्तविक समय सतर्कता प्रणाली स्थापित करना;
- (झ) अन्वेषण, ऊपरी अधिकारियों तक पहुँच और नियामक रिपोर्टिंग की प्रक्रियाओं सहित चिह्नित सतर्कता मामलों से निपटने के लिए परिभाषित प्रक्रियाएँ बनाना;
- (ञ) प्रतिभागियों के लिए सुरक्षित संचार चैनलों का उपयोग करके इलेक्ट्रॉनिक ट्रेडिंग प्लेटफॉर्म से जुड़ने हेतु आवश्यक व्यवस्था करना;
- (ट) प्रतिभागियों का व्यापक नेटवर्क बनाने की क्षमता रखना, और प्रतिभागियों को शामिल करने और उन्हें विनियमित करने के लिए पर्याप्त सुविधाएँ रखना;
- (ठ) इलेक्ट्रॉनिक ट्रेडिंग प्लेटफॉर्म पर किए गए ट्रेड से उत्पन्न शिकायतों के समाधान के लिए, प्राधिकरण द्वारा समय-समय पर यथा-निर्दिष्ट तरीके और रूप में तंत्र स्थापित करना:
बशर्ते कि इलेक्ट्रॉनिक ट्रेडिंग प्लेटफॉर्म पर किए गए ट्रेड के निपटान से या उससे संबंधित किसी भी विवाद के समाशोधन और निपटान लागू कानूनों और संचालन नीति के अनुसार किया जाएगा;
- (ड) वास्तविक समय में ट्रेड, मात्रा और भावों के बारे में सूचना प्रसारित करने की रखना;
- (ढ) पर्याप्त व्यावसायिक और अन्य संबंधित अनुभव रखने वाले व्यक्तियों की पर्याप्त संख्या में नियुक्ति करना;
- (ण) यदि पहले दी गई जानकारी में कोई उल्लेखनीय परिवर्तन होता है, तो तुरंत सक्षम अधिकारी को लिखित रूप में तत्काल सूचित करें; और
- (थ) प्राधिकरण द्वारा यथा-निर्दिष्ट किसी भी अन्य अपेक्षाओं का पालन करें।

11. इलेक्ट्रॉनिक ट्रेडिंग प्लेटफॉर्म पर भागीदारी

- (1) संस्थान, चाहे विनियमित हों या अविनियमित, संपदा ट्रेड फर्म, निधियाँ, परिवार कार्यालय और निक्षेपागार केन्द्रों सहित, प्रत्येक व्यक्ति प्रतिभागी के रूप में शामिल किए जाने के लिए पात्र होगा।

स्पष्टीकरण: किसी भी संदेह को दूर करने के लिए, यह स्पष्ट किया जाता है कि विदेश मुद्रा विनियम प्रबंधन अधिनियम, 1999 (1999 का 42) के अधीन भारत में रहने वाले किसी व्यक्ति को भी प्रतिभागी के रूप में शामिल किया जा सकता है, यदि उस व्यक्ति को उक्त अधिनियम या

भारत में उस समय लागू किसी अन्य कानून के उपबंधों के अधीन भारत के बाहर योग्य लिखतों में लेनदेन करने की अनुमति हो।

- (2) इलेक्ट्रॉनिक ट्रेडिंग प्लेटफॉर्म ऑपरेटर किसी व्यक्ति को प्रतिभागी के रूप में शामिल करने के लिए निष्पक्ष, पारदर्शी और बिना भेदभाव वाले मानदंड निर्धारित करेगा।
- (3) किसी व्यक्ति को प्रतिभागी के रूप में शामिल करने से पहले, इलेक्ट्रॉनिक ट्रेडिंग प्लेटफॉर्म ऑपरेटर यह सुनिश्चित करने के लिए आवश्यक जांच-पड़ताल करेगा कि वह व्यक्ति:
 - (क) सुप्रतिष्ठित हो;
 - (ख) इलेक्ट्रॉनिक ट्रेडिंग प्लेटफॉर्म पर लेनदेन करने में पर्याप्त क्षमता और अनुभव रखता हो; और
 - (ग) अपने कामकाज के ढंग से वित्तीय और तकनीकी संसाधनों सहित आवश्यक संगठनात्मक व्यवस्थाएं रखता हो।
- (4) इलेक्ट्रॉनिक ट्रेडिंग प्लेटफॉर्म ऑपरेटर अपने प्रतिभागियों की पहचान विधिक एंटीटी पहचानपत्र, स्थायी खाता संख्या (पीएएन) या किसी अन्य समान दस्तावेज़ का प्रयोग करके करेगा।

12. इलेक्ट्रॉनिक ट्रेडिंग प्लेटफॉर्म पर ट्रेड किए जाने वाले उत्पाद

इलेक्ट्रॉनिक ट्रेडिंग प्लेटफॉर्म ऑपरेटर इलेक्ट्रॉनिक ट्रेडिंग प्लेटफॉर्म पर केवल विनियम 5 के उप-विनियम (2) के खंड (क) के अधीन विनिर्दिष्ट योग्य लिखतों में ट्रेडिंग की अनुमति देगा।

13. परिचालन नीति

- (1) इलेक्ट्रॉनिक ट्रेडिंग प्लेटफॉर्म ऑपरेटर अपने बोर्ड द्वारा अनुमोदित ऐसी परिचालन नीति लागू करेगा जो:
 - (क) वस्तु-निष्ठ, पारदर्शी और निष्पक्ष होगी; और
 - (ख) प्रत्येक प्रतिभागी पर कानूनी रूप से बाध्यकारी और प्रभावी हो।
- (2) परिचालन नीति में अन्य बातों के साथ-साथ निम्नांकित हेतु प्रावधान होंगे:
 - (क) इलेक्ट्रॉनिक ट्रेडिंग प्लेटफॉर्म ऑपरेटर पर प्रतिभागियों को शामिल करना और उन्हें निलंबित और निष्कासित करना,
 - (ख) इलेक्ट्रॉनिक ट्रेडिंग प्लेटफॉर्म ऑपरेटर की भूमिका और उत्तरदायित्व,
 - (ग) नीति के उल्लंघन की स्थिति में प्रतिभागियों के लिए देयता ढांचा,
 - (घ) इलेक्ट्रॉनिक ट्रेडिंग प्लेटफॉर्म का उपयोग करने के लिए लागू होने वाले प्रतिबंध या अन्य अपेक्षाएं,
 - (ङ) आदेशों का संसाधन और निष्पादन, और जोखिम प्रबंधन और नियंत्रण तथा
 - (च) प्रतिभागियों के लिए शिकायत निवारण और विवाद समाधान ढांचा।
- (3) अपनी परिचालन नीति में महत्वपूर्ण परिवर्तन सक्षम प्राधिकारी को सूचित किए जाएंगे।

स्पष्टीकरण: इस उप-विनियम के उद्देश्यों के लिए, "महत्वपूर्ण परिवर्तन" का तात्पर्य इलेक्ट्रॉनिक ट्रेडिंग प्लेटफॉर्म ऑपरेटर के अपने संविदात्मक उत्तरदायित्वों को पूरा करने की क्षमता को प्रभावित करने वाली इलेक्ट्रॉनिक ट्रेडिंग प्लेटफॉर्म की प्रक्रियाओं, प्रणालियों, प्रदर्शन मानकों, सुरक्षा अपेक्षाओं या नीतियों में बड़ा परिवर्तन होगा।

(4) इलेक्ट्रॉनिक ट्रेडिंग प्लेटफॉर्म ऑपरेटर यह सुनिश्चित करने के लिए कि इसके इलेक्ट्रॉनिक ट्रेडिंग प्लेटफॉर्म भागीदार नीतियों और प्रक्रियाओं सहित, पर्याप्त और प्रभावी प्रणालियां और नियंत्रण स्थापित करके उनका अनुरक्षण सुनिश्चित करने के लिए परिचालन नीति का पालन करेंगे।

(5) इलेक्ट्रॉनिक ट्रेडिंग प्लेटफॉर्म ऑपरेटर उस नीति में चिह्नित कमियों या त्रुटियों को तुरंत दूर करेगा।

(6) इलेक्ट्रॉनिक ट्रेडिंग प्लेटफॉर्म ऑपरेटर अपनी नीति को, अन्य बातों के साथ-साथ, अपनी आधिकारिक वेबसाइट पर डालकर जनता के लिए उपलब्ध कराएगा।

14. जोखिम प्रबंधन

(1) इलेक्ट्रॉनिक ट्रेडिंग प्लेटफॉर्म ऑपरेटर:

(क) जोखिमों के व्यापक प्रबंधन के लिए सुदृढ़ जोखिम प्रबंधन प्रणाली और अवसंरचना तैयार करेगा, और यह सुनिश्चित करेगा कि उसके संचालन से जुड़े जोखिमों की सही पहचान की जाए और समझदारी से उनका प्रबंधन किया जाए।

(ख) अपने प्रतिभागियों के लिए एक्सेस नियंत्रण उपाय लागू करेगा और इलेक्ट्रॉनिक ट्रेडिंग प्लेटफॉर्म पर अनधिकृत एक्सेस को रोकने के लिए कदम उठाएगा।

(ग) प्रभावी प्रणालियां, नियंत्रण और प्रक्रियाएं उपलब्ध करेगा ताकि:

(i) यह सुनिश्चित किया जा सके कि उसकी ट्रेडिंग प्रणालियां सुदृढ़ हों, उनमें अधिकतम आदेश और संदेश मात्रा से निपटने की पर्याप्त क्षमता हो, और वे बाजार की तनावपूर्ण परिस्थिति में भी व्यवस्थित तरीके से कार्य कर सकें।

(ii) उन आदेशों को निरस्त कर सकें जो पहले से निर्धारित मात्रा और मूल्य की सीमा से अधिक हों, और अपनी सुविधा पर ट्रेड होने वाले उपयुक्त लिखतों के ट्रेड को, जब उन लिखतों की कीमत में बहुत अधिक उतार-चढ़ाव हो, कुछ समय के लिए रोक सकें।

(iii) त्रुटिपूर्ण ट्रेड को रोका और कम किया जा सके, ऐसी त्रुटियों का तुरंत पता लगाकर उन्हें ठीक किया जा सके और यह निर्धारित किया जा सके कि ये त्रुटियाँ बाजार की अव्यवस्थित गतिविधियों से जुड़ी हैं या नहीं।

(घ) अपने इलेक्ट्रॉनिक ट्रेडिंग प्लेटफॉर्म पर या उसके माध्यम से होने वाले बाजार दुरुपयोग की पहचान करने, उसे रोकने और उससे बचाव के लिए उचित उपाय लागू करेगा और उनका रखरखाव करेगा और प्राधिकरण को किसी भी बाजार दुरुपयोग की तुरंत सूचना देगा।

(2) जहां इलेक्ट्रॉनिक ट्रेडिंग प्लेटफॉर्म ऑपरेटर प्रतिभागियों को एल्गोरिथ्मिक ट्रेडिंग सिस्टम (एटीएस) के माध्यम से इलेक्ट्रॉनिक ट्रेडिंग प्लेटफॉर्म तक पहुँचने की अनुमति देता है, उसे यह सुनिश्चित करना चाहिए कि:

- (क) ऐसी पहुँच के बारे में इलेक्ट्रॉनिक ट्रेडिंग प्लेटफ़ॉर्म पर अन्य प्रतिभागियों को जानकारी दी जाए;
- (ख) ऐसी पहुँच एल्गोरिथ्मिक ट्रेडिंग सिस्टम को प्लेटफ़ॉर्म तक पहुँचने की अनुमति तभी दी जाए जब परीक्षण द्वारा सुनिश्चित कर लिया जाए कि इसकी भागीदारी से प्लेटफ़ॉर्म के सामान्य कामकाज पर कोई असर नहीं पड़ेगा; और
- (ग) एल्गोरिथ्मिक ट्रेडिंग सिस्टम को संचालित करने के लिए भागीदार द्वारा तैनात किए गए कार्मिक इसे संचालित करने के लिए पर्याप्त रूप से प्रशिक्षित और उपयुक्त हों।

15. समाशोधन और निपटान

(1) इलेक्ट्रॉनिक ट्रेडिंग प्लेटफ़ॉर्म ऑपरेटर, जो अपने इलेक्ट्रॉनिक प्रणाली के माध्यम से दो या उससे अधिक प्रतिभागियों के बीच योग्य लिखतों में लेनदेन की समाशोधन और निपटान की सुविधा देता है, वह यह सुनिश्चित करेगा कि ऐसे इलेक्ट्रॉनिक प्रणाली पर या उसके माध्यम से किए गए लेनदेन में शामिल पक्षों के अधिकारों और देयताओं को समय पर पूरा करने के लिए संतोषजनक व्यवस्था हों और वह अपने प्रतिभागियों को इन व्यवस्थाओं और उनमें होने वाले किसी भी परिवर्तन की जानकारी प्रदान करेगा।

(2) इलेक्ट्रॉनिक ट्रेडिंग प्लेटफ़ॉर्म ऑपरेटर द्वारा किसी एंटीटी के साथ उप-विनियम (1) में संदर्भित व्यवस्थाएं प्राधिकरण की पूर्व-स्वीकृति से की जाएंगी।

बशर्ते, यदि कोई इलेक्ट्रॉनिक ट्रेडिंग प्लेटफ़ॉर्म ऑपरेटर निधि समाशोधन और/या निपटान सुविधा की पेशकश करना चाहता है, तो ऐसी सेवा शुरू करने से पहले उसे अंतरराष्ट्रीय सेवा केंद्र प्राधिकरण (भुगतान और निपटान प्रणाली) विनियम, 2024 के अधीन भुगतान प्रणाली ऑपरेटर के रूप में अंतरराष्ट्रीय वित्तीय सेवा केंद्र से स्वीकृति लेनी होगी।

अध्याय IV

इलेक्ट्रॉनिक ट्रेडिंग प्लेटफ़ॉर्म ऑपरेटर के सामान्य दायित्व

16. कारोबार निरंतरता योजना और आपदा बचाव साइट

इलेक्ट्रॉनिक ट्रेडिंग प्लेटफ़ॉर्म ऑपरेटर डेटा और लेनदेन निष्ठा बनाए रखने और अपने कामकाज को लगातार जारी रखने के लिए ट्रेडिंग निरंतरता योजना और आपदा बचाव साइट बनाएगा और उसे इसका अनुरक्षण करेगा।

17. साइबर सुरक्षा और साइबर प्रतिरोधक क्षमता

इलेक्ट्रॉनिक ट्रेडिंग प्लेटफ़ॉर्म ऑपरेटर प्राधिकरण द्वारा समय-समय निर्दिष्ट साइबर सुरक्षा और साइबर प्रतिरोधक क्षमता अपेक्षाओं का पालन करेगा।

18. अनुपालन अधिकारी की नियुक्ति

इलेक्ट्रॉनिक ट्रेडिंग प्लेटफ़ॉर्म ऑपरेटर लागू नियामक अपेक्षाओं का पालन सुनिश्चित करने के लिए उत्तरदायी अनुपालन अधिकारी नियुक्त करेगा।

अध्याय V

विविध

19. डेटा परिरक्षण, पहुँच और उपयोग

(1) इलेक्टोनिक् ट्रेडिंग प्लेटफ़ॉर्म ऑपरेटर यह सुनिश्चित करेगा कि इलेक्टोनिक् ट्रेडिंग प्लेटफ़ॉर्म पर गतिविधियों से जुड़े सभी डेटा की गोपनीयता और सुरक्षा बनी रहे, और ऐसे डेटा तक पहुँच पूरी तरह से उसके नियंत्रण में हो।

(2) इलेक्टोनिक् ट्रेडिंग प्लेटफ़ॉर्म ऑपरेटर इलेक्टोनिक् ट्रेडिंग प्लेटफ़ॉर्म पर गतिविधियों से जुड़े सभी डेटा को आसानी से हासिल किए जा सकने वाले रूप में कम से कम आठ (8) वर्षों तक सुरक्षित रखेगा:

बशर्ते कि विधि अनुसार प्राधिकरण द्वारा किसी जाँच के संबंध में माँगा गया डेटा, ऐसी जाँच पूरी होने की तारीख से कम से कम तीन (3) वर्षों तक अनुरक्षित रखा जाएगा।

बशर्ते यह भी कि किसी समय विशेष पर लागू कानूनों के अधीन अन्वेषक अभिकरण द्वारा किसी अन्वेषण के लिए के संबंध में माँगे गए डाटा को ऐसे कानून के अधीन निर्धारित अवधि के लिए अनुरक्षित किया जाएगा।

(3) यदि प्राधिकरण रजिस्ट्रीकरण निरस्त कर देता है या इलेक्टोनिक् ट्रेडिंग प्लेटफ़ॉर्म ऑपरेटर रजिस्ट्रीकरण अभ्यर्पित कर देता है, तो प्राधिकरण इलेक्टोनिक् ट्रेडिंग प्लेटफ़ॉर्म ऑपरेटर को निदेश दे सकता है कि वह इलेक्टोनिक् ट्रेडिंग प्लेटफ़ॉर्म पर होने वाली गतिविधियों से जुड़ा सारा डेटा प्राधिकरण या प्राधिकरण द्वारा यथा-निर्दिष्ट किसी अन्य अभिकरण के साथ साझा करेगा।

20. रिटर्न और रिपोर्ट

(1) इलेक्टोनिक् ट्रेडिंग प्लेटफ़ॉर्म ऑपरेटर को प्राधिकरण द्वारा यथा-निर्दिष्ट प्रारूप और ढंग से रिटर्न, विवरण और जानकारी देनी होगी।

(2) विनियम 3 के प्रति किसी भ्रान्ति के बिना, इलेक्टोनिक् ट्रेडिंग प्लेटफ़ॉर्म को संचालित करने वाली अंतरराष्ट्रीय वित्तीय सेवा केंद्र की बैंक इकाई प्राधिकरण द्वारा यथा-निर्दिष्ट प्रारूप और विधि से रिटर्न, विवरण और जानकारी देनी होगी।

(3) इलेक्टोनिक् ट्रेडिंग प्लेटफ़ॉर्म ऑपरेटर को अपने लेखापरीक्षित वार्षिक वित्तीय विवरण, उनको अंतिम रूप दिए जाने के तीस (30) दिनों के भीतर प्राधिकरण को प्रस्तुत करने होंगे।

21. सूचना मांगने का अधिकार

प्राधिकरण किसी भी समय इलेक्टोनिक् ट्रेडिंग प्लेटफ़ॉर्म ऑपरेटर से कोई भी जानकारी, दस्तावेज़ या रिकॉर्ड मांग सकता है, और इलेक्टोनिक् ट्रेडिंग प्लेटफ़ॉर्म ऑपरेटर को निर्धारित समय के भीतर उसे प्रस्तुत करना होगा।

22. निरीक्षण, पूछताछ, अन्वेषण और लेखापरीक्षा

(1) प्राधिकरण किसी भी समय इलेक्टोनिक् ट्रेडिंग प्लेटफ़ॉर्म ऑपरेटर का निरीक्षण, अन्वेषण, पूछताछ या लेखापरीक्षा कर सकता है।

(2) इलेक्टोनिक् ट्रेडिंग प्लेटफ़ॉर्म ऑपरेटर के प्रत्येक प्रबंधक, निदेशक, प्रबंध निदेशक, अध्यक्ष, अधिकारी और अन्य कार्मिक का यह उत्तरदायित्व होगा कि वह ऐसे इलेक्टोनिक् ट्रेडिंग प्लेटफ़ॉर्म ऑपरेटर के निरीक्षण, पूछताछ, अन्वेषण या लेखापरीक्षा के दौरान प्राधिकरण का सहयोग करेगा।

(3) इलेक्ट्रॉनिक ट्रेडिंग प्लेटफॉर्म ऑपरेटर के निरीक्षण, पूछताछ, अन्वेषण या लेखापरीक्षा से प्राप्त रिपोर्ट पर विचार करने के बाद, प्राधिकरण जो भी उचित समझे, कार्रवाई कर सकता है।

23. प्राधिकरण द्वारा निदेश

अधिनियम और उसके अधीन जारी नियमों, विनियम या सहायक निदेशों के अधीन अपनी शक्तियों का प्रयोग करते हुए, प्राधिकरण स्वयं या कोई जानकारी मिलने पर या किसी निरीक्षण, पूछताछ या अन्वेषण के दौरान या उसके पूरा होने पर, जनमानस या ट्रेडिंग या प्रतिभागियों या अंतरराष्ट्रीय वित्तीय सेवा केंद्र में इलेक्ट्रॉनिक ट्रेडिंग प्लेटफॉर्म के कामकाज के हित में, यथोचित निदेश जारी कर सकता है।

24. प्राधिकरण द्वारा लेखापरीक्षक की नियुक्ति

प्राधिकरण, इलेक्ट्रॉनिक ट्रेडिंग प्लेटफॉर्म ऑपरेटर की खाता-बहियों, रिकॉर्ड, दस्तावेज़, अवसंरचना, प्रणाली, प्रक्रियाओं या कामकाज की लेखापरीक्षा करने के लिए लेखापरीक्षक नियुक्ति, यथोचित विधि से कर सकता है।

25. व्यय की वसूली का प्राधिकार

प्राधिकरण को इलेक्ट्रॉनिक ट्रेडिंग प्लेटफॉर्म ऑपरेटर से इलेक्ट्रॉनिक ट्रेडिंग प्लेटफॉर्म ऑपरेटर की खाता-बहियों, रिकॉर्ड, दस्तावेज़, अवसंरचना, प्रणाली या प्रक्रियाओं के निरीक्षण या अन्वेषण के उद्देश्य से लेखापरीक्षक को दिए गए शुल्क सहित किए गए व्यय को वसूल करने का अधिकार होगा।

26. कठिनाइयों को दूर करने का अधिकार

इन विनियम के उपबंधों की व्याख्या या लागू करने में किसी भी कठिनाई को दूर करने के लिए, प्राधिकरण मार्गदर्शी नोट या परिपत्र के माध्यम से निदेश जारी कर सकता है।

27. नियमों का कड़ाई से प्रवर्तन में ढील देने की शक्ति

(1) प्राधिकरण, लिखित कारणों के आधार पर और अंतरराष्ट्रीय वित्तीय सेवा केंद्र में वित्तीय सेवा बाजार के विकास के हित में, इन नियमों की किसी भी अपेक्षा को कड़ाई से प्रवर्तन करने में ढील दे सकता है।

(2) उप-विनियम (1) के अधीन ढील पाने के लिए, प्राधिकरण के पास आवेदन प्रस्तुत करना होगा जिसमें पूरी जानकारी और वे कारण बताए गए हों जिनके आधार पर ढील मांगी जा रही है; साथ ही, यूएसडी 1500 का शुल्क भी जमा कराना होगा।

28. विधि विनिर्दिष्ट करने और स्पष्टीकरण जारी करने का अधिकार

प्राधिकरण, इन नियमों को लागू करने और उनसे जुड़े मामलों के लिए, या अंतरराष्ट्रीय वित्तीय सेवा केंद्र में इलेक्ट्रॉनिक ट्रेडिंग प्लेटफॉर्म से संबंधित कार्यकलापों को आसान और विनियमित करने के लिए, सहायक अनुदेशों के माध्यम से मानकों, प्रक्रियाओं, तौर-तरीकों, अतिरिक्त अपेक्षाओं, दिशानिर्देशों को निर्धारित कर सकता है और यथोपेक्षित स्पष्टीकरण दे सकता है।

प्रथम अनुसूची
योग्य क्षेत्राधिकार

[विनियम 2 के उप-विनियम (1) का खंड (च) देखें]

संख्या	क्षेत्राधिकार	प्राधिकरण
1.	सिंगापुर	मॉनेटरी अथॉरिटी ऑफ़ सिंगापुर द्वारा जारी 'सिक्युरिटीज एंड फ्यूचर्स रेगुलेशन्स (ऑर्गनाइज़्ड मार्केट्स), 2018' के अधीन मान्यता प्राप्त मार्केट ऑपरेटर।
2.	भारत	भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा जारी मास्टर निदेश – भारतीय रिजर्व बैंक (इलेक्ट्रॉनिक ट्रेडिंग प्लेटफॉर्म) निदेश, 2025 के अधीन इलेक्ट्रॉनिक ट्रेडिंग प्लेटफॉर्म
3.	संयुक्त राज्य अमेरिका	सिक्युरिटीज एंड एक्सचेंज कमीशन द्वारा आरईजी. – एटीएस के अधीन स्वीकृत की गई वैकल्पिक ट्रेडिंग प्रणाली।
4.	यूनाइटेड किंगडम	फ़ाइनेंशियल कंडक्ट अथॉरिटी (एफसीए) यूके द्वारा अधिकृत मल्टीलेटरल ट्रेडिंग फ़ैसिलिटी (एमटीएफ)।
5.	यूरोपियन यूनियन	'मार्केट्स इन फ़ाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट्स डायरेक्टिव II' के अधीन कार्य करने वाली और उस ईयू देश की नेशनल कॉम्पिटेंट अथॉरिटी द्वारा अधिकृत और निगरानी की जाने वाली मल्टीलेटरल ट्रेडिंग फ़ैसिलिटी (एमटीएफ) जहाँ यह वेन्यू रजिस्ट्रीकृत है और कार्य कर रहा है।
6.	दुबई इंटरनेशनल सेंटर (डीआईएफसी)	डीआईएफसी में ऑथोराइज़्ड मार्केट इंस्टीट्यूशन (एएमआई) जिसे निवेश के लिए वैकल्पिक ट्रेडिंग प्रणाली संचालित करने की स्वीकृति मिली है।

द्वितीय अनुसूची

उपयुक्त और समुचित अपेक्षाएं

[विनियम 4 का खंड (ग) देखें]

कोई व्यक्ति उपयुक्त और समुचित माना जाएगा यदि:-

(क) उस व्यक्ति का निष्पक्षता और निष्ठा का रिकॉर्ड हो, जिसमें निम्नांकित शामिल हैं किन्तु इन्हीं तक सीमित नहीं हैं:

- (i) वित्तीय निष्ठा;
- (ii) अच्छी प्रतिष्ठा और चरित्र; और
- (iii) ईमानदारी।

(ख) उस व्यक्ति पर इनमें से कोई भी अयोग्यता लागू न हो –

- (i) व्यक्ति को किसी न्यायालय ने अनैतिक आचरण, किसी आर्थिक अपराध, या वित्तीय बाज़ारों और वित्तीय संस्थानों से जुड़े कानूनों के अधीन किसी अपराध के लिए दोषी ठहराया हो;
- (ii) किसी वित्तीय नियामक प्राधिकरण ने उस व्यक्ति के विरुद्ध वसूली की कार्यवाही शुरू की हो और वह अभी भी लंबित हो;

- (iii) गलत कार्य के लिए उस व्यक्ति के विरुद्ध कंपनी बंद करने का आदेश पारित किया गया हो;
- (iv) व्यक्ति को 'घोषित दिवालिया' घोषित न किया गया हो;
- (v) किसी नियामक प्राधिकरण ने उस व्यक्ति को वित्तीय उत्पाद या वित्तीय सेवाओं का उपयोग करने, उन्हें उपलब्ध कराने या उनमें लेन-देन करने से रोकने या प्रतिबंधित करने का आदेश जारी किया हो, और उस आदेश में निर्दिष्ट अवधि समाप्त होने की तारीख से तीन वर्ष की अवधि व्यतीत न हुई हो;
- (vi) प्राधिकरण या किसी अन्य नियामक प्राधिकरण ने उस व्यक्ति के विरुद्ध कोई अन्य आदेश पारित किया हो, और आदेश की तारीख से तीन वर्ष की अवधि व्यतीत न हुई हो;
- (vii) सक्षम क्षेत्राधिकार वाले न्यायालय ने व्यक्ति को मानसिक रूप से अस्वस्थ पाया हो और यह निष्कर्ष अभी भी लागू हो;
- (viii) व्यक्ति आर्थिक रूप से सुदृढ़ न हो या उसे जानबूझकर भुगतान न करने वाले व्यक्ति के रूप में वर्गीकृत किया गया हो;
- (ix) व्यक्ति को भगोड़ा आर्थिक अपराधी घोषित किया गया हो; या
- (x) प्राधिकरण द्वारा विनिर्दिष्ट कोई अन्य अयोग्यता।

प्रवीण त्रिवेदी, कार्यकारी निदेशक

[विज्ञापन-III/4/असा./322/2026-27]

INTERNATIONAL FINANCIAL SERVICES CENTRES AUTHORITY

NOTIFICATION

Gandhinagar, the 8th September, 2026

INTERNATIONAL FINANCIAL SERVICES CENTRES AUTHORITY (ELECTRONIC TRADING PLATFORMS) REGULATIONS, 2026

F. No. IFSCA/GN/2026/ 016.— *In exercise of the powers conferred by sub-section (1) of section 28 read with sub-section (1) of section 12 and sub-section (1) of section 13 of the International Financial Services Centres Authority Act, 2019 (50 of 2019); section 45W of the Reserve Bank of India Act, 1934 (2 of 1934), the International Financial Services Centres Authority hereby makes the following regulations, namely :-*

CHAPTER I

PRELIMINARY

1. Short title and commencement

- (1) These regulations may be called the International Financial Services Centres Authority (Electronic Trading Platforms) Regulations, 2026.
- (2) These regulations shall come into force on and from the date of their publication in the Official Gazette.

2. Definitions.

- (1) In these regulations, unless the context otherwise requires, the terms defined herein shall bear the meanings as assigned below, and their cognate expressions shall be construed accordingly, -

- (a) "Act" means the International Financial Services Centres Authority Act, 2019 (50 of 2019);
- (b) "Algorithmic Trading Systems (ATS)" means the hardware, software, procedures, and processes used to originate a transaction on an Electronic Trading Platform using a system-driven execution mechanism;
- (c) "Authority" means the International Financial Services Centres Authority established under sub-section (1) of section 4 of the Act;
- (d) "Competent Authority" means,—
 - (i) Chairperson;
 - (ii) Whole-Time Member or Committee of the Whole-Time Members or officer(s) of the Authority, as may be determined by the Chairperson;
- (e) "Eligible Instruments" means securities, money market instruments, foreign exchange, and derivatives as defined in the Reserve Bank of India Act, 1934, or other instruments of a like nature, as may be specified by the Authority from time to time.

Explanation: For the removal of doubts, it is hereby clarified that the scope of this definition shall also include the instruments mentioned in this clause which are denominated in Indian Rupee but settled in a specified foreign currency.

- (f) "Eligible Jurisdiction" shall mean the jurisdictions specified in the First Schedule;
- (g) "Electronic Trading Platform" means an electronic system located in the International Financial Services Centre through which offers for sale, purchase or exchange of Eligible Instruments are regularly made by the Participants and which, upon acceptance of such offer, may enable the clearing and settlement of such Eligible Instruments between the Participants;
- (h) "Electronic Trading Platform Operator (ETP Operator)" means an entity that has been granted registration under sub-regulation (2) of regulation 5 to operate an Electronic Trading Platform;
- (i) "International Financial Services Centre (IFSC)" shall have the same meaning as assigned to it under clause (g) of sub-section (1) of Section 3 of the Act;
- (j) "Key Managerial Personnel" shall have the same meaning as assigned to it in clause (51) of section 2 of the Companies Act, 2013 (18 of 2013);
- (k) "Market Abuse" for the purpose of these Regulations, shall mean any action by a Participant on an Electronic Trading Platform, whether executed manually or through an Algorithmic Trading System, with the intention to unreasonably disadvantage other Participant(s), distort the pricing mechanisms on an ETP, or create artificial supply and demand for Eligible Instruments;
- (l) "Net Worth" for the purpose of these Regulations, shall mean paid-up equity capital, compulsorily convertible preference shares, free reserves, balance in share premium account and capital reserves representing surplus arising out of sale proceeds of assets, but not include reserves created by revaluation of assets adjusted for accumulated loss balance, book value of intangible assets and deferred revenue expenditure, if any;

Explanation: For the removal of doubts, it is clarified that compulsorily convertible preference shares shall mean preference shares, whether cumulative or non-cumulative, which are compulsorily convertible into equity shares, and the shareholder agreement(s) must specifically prohibit the withdrawal of such preference capital at any time.

- (m) "Participant" means a person transacting in the Eligible Instruments through an ETP;

(2) Words and expressions used and not defined in these regulations but defined in the Act, Reserve Bank of India Act, 1934 (2 of 1934), the Banking Regulation Act, 1949 (10 of 1949), or the Companies Act, 2013 (18 of 2013), or any rules or regulations made thereunder shall have the same meanings respectively assigned to them in those Acts, rules or regulations made thereunder or any statutory modification or re-enactment thereto, as the case may be.

CHAPTER II

REGISTRATION

3. Application for seeking registration.

(1) No person shall operate an Electronic Trading Platform in the IFSC unless it has obtained a registration, as an Electronic Trading Platform Operator, under these regulations:

Provided that an IFSC Banking Unit shall not be required to obtain the registration if such Unit or its parent bank, as the case may be, is:—

- a) the sole provider of buy or sell quotes in Eligible Instrument(s) on its Electronic Trading Platform; and
- b) one of the counterparties to every transaction undertaken through such Electronic Trading Platform.

Provided further that a person operating an electronic trading platform located outside the International Financial Services Centre and providing services to an entity in the International Financial Services Centre shall not be required to obtain a registration as an Electronic Trading Platform Operator, under these Regulations.

(2) A company incorporated in the International Financial Services Centre shall be eligible to seek registration to act as an Electronic Trading Platform Operator :

Provided that an entity operating an electronic trading platform, by whatever name called, in an Eligible Jurisdiction may setup a branch in the International Financial Services Centre and obtain registration from the Authority under these Regulations:

Provided further that a financial institution set up in the International Financial Services Centre may also be eligible to obtain certificate of registration, subject to such terms and conditions as may be specified by the Authority.

(3) An application for certificate of registration to act as an Electronic Trading Platform Operator shall be submitted to the Authority in such form and manner, along with such fees, as may be specified by the Authority.

4. Requirements for grant of registration

(1) The Authority, while examining the application filed under regulation 3, shall take into account such factors as it considers relevant for the grant of certificate of registration, including the following:

- (a) track record, management expertise and financial soundness of the applicant or its promoter(s);
- (b) ability to employ sufficient number of individuals having adequate professional and other relevant experience;
- (c) the directors, Key Managerial Personnel, and persons exercising control over the applicant i.e., the natural persons who ultimately own, control, or significantly influence the applicant's operations, assets, or strategic decisions satisfy the “fit and proper” criteria as specified in the Second Schedule;

Explanation: For the removal of doubts, it is clarified that the applicant seeking certificate of registration shall ensure that such persons are “fit and proper”, at all times, during the validity of its registration.

- (d) strength of risk management systems and accompanying internal controls;
- (e) ability to satisfy the Net Worth requirements specified in these regulations;
- (f) viability of the business plan and projections submitted by the applicant.

5. Grant of registration

(1) Upon considering an application for certificate of registration, if the Authority is satisfied that the applicant, *prima facie*, fulfils the conditions for grant of registration, the Authority may issue an “in-principle approval” with or without additional conditions to be fulfilled by the applicant, prior to the grant of registration:

Provided that the “in-principle approval” granted to an applicant may be revoked by the Authority if the applicant is unable to fulfil with the condition(s) specified in the “in-principle approval”, to the satisfaction of the Authority.”

(2) The Authority may, upon being satisfied that the applicant fulfilled the requirements specified under these regulations, including the additional conditions imposed, if any, while granting “in-principle approval” grant registration to the applicant to operate as Electronic Trading Platform Operator subject to such conditions as the Authority may deem fit, and also specify the following:

- (a) the Eligible Instrument(s) that may be offered for sale, purchase or exchange on the Electronic Trading Platform ; and
- (b) the categories of persons eligible to be Participants of such platform.

(3) In addition to the conditions specified in sub-regulation (2), an Electronic Trading Platform Operator shall also comply with such other conditions as may be specified by the Authority from time to time.

(4) The registration granted under sub-regulation (2) shall remain valid till it is cancelled by the Authority or surrendered by the Electronic Trading Platform Operator.

6. Refusal to grant registration

(1) If the Authority, upon examination of the application, is of the opinion that the certificate of registration cannot be granted, it shall communicate the deficiencies to the applicant, giving it thirty days' time to rectify them:

Provided that the Authority may, in its sole discretion, extend the aforesaid period of thirty days to such further period as it may deem fit.

Provided further that no such extension shall be granted beyond a period of ninety days without the permission of the Chairperson who may extend such period up to one-hundred and eighty days, for the reasons to be recorded in writing.

(2) If the applicant fails to rectify the deficiencies to the satisfaction of the Authority within the specified time, the Authority shall refuse to grant the registration and communicate the same to the applicant, with reasons thereof:

Provided that no such refusal shall be made without giving the applicant a reasonable opportunity of being heard by way of filing written submissions.

(3) The applicant whose application is refused under sub-regulation (2) may submit a fresh application for registration after a period of six (6) months from the date of communication of such refusal by the Authority.

7. Suspension or Cancellation of registration

If the Authority is satisfied that an Electronic Trading Platform Operator has failed to comply with any of the conditions of its certificate of registration, provisions of these regulations, order or direction issued by the Authority, or that the activity of the Electronic Trading Platform Operator is being carried on in a manner prejudicial to the interests of the Participants, it may suspend or cancel the registration granted to such Electronic Trading Platform Operator:

Provided that the no order for suspension or cancellation of the registration shall be issued without giving such Electronic Trading Platform Operator a reasonable opportunity of being heard by way of filing written submissions.

8. Surrender of registration

(1) An Electronic Trading Platform Operator may file an application to the Authority for surrender of its registration with the Authority, in such form and manner as may be specified.

(2) Upon examination of the application filed under sub-regulation (1) and being satisfied that the surrender of registration is unlikely to cause any material adverse effect on the financial services market in the International Financial Services Centre or the interests of the Participants, the Authority may permit such surrender, subject to such conditions as it may deem fit.

(3) The surrender of registration shall become effective only upon its acceptance by the Authority.

9. Net Worth requirements

(1) An Electronic Trading Platform Operator set up as a company in the IFSC shall, at all times, , maintain a Net Worth of at least USD 200,000 or its equivalent in any specified foreign currency.

(2) An Electronic Trading Platform Operator set up as a branch shall, at all times, maintain a Net Worth of at least USD 200,000 or its equivalent in any specified foreign currency, with its parent.

(3) As a risk management measure, the Authority may specify a higher Net Worth requirement for an Electronic Trading Platform Operator, at any time, having regard to the nature and scale of its business.

(4) An Electronic Trading Platform Operator shall, within six months from the closure of every financial year, submit an audited Net Worth certificate to the Authority.

(5) In case of any shortfall in the Net Worth as specified in this regulation, the Electronic Trading Platform Operator shall immediately restore the same and report compliance of the same within a period of fifteen days the occurrence of such event, to the Competent Authority.

Chapter III

OPERATING GUIDELINES

10. General obligations

An ETP Operator shall:

- (a) lay down and maintain transparent rules and procedures for ensuring fair and orderly trading on the Electronic Trading Platform;
- (b) lay down objective criteria and put in place the necessary infrastructure for the orderly and efficient execution of orders;
- (c) establish and maintain arrangements for the sound management of the technical operations of the Electronic Trading Platform, including effective business continuity arrangements to address the risks of systemic disruption;
- (d) lay down and maintain transparent rules regarding the criteria for determining the Eligible Instruments that can be traded on the ETP;
- (e) develop a mechanism to provide, access to, sufficient publicly available information to enable its Participants to take a well-informed investment decision, in relation to, the nature of the Participants and the type of Eligible Instrument traded;
- (f) lay down and maintain a comprehensive policy of managing conflicts of interest, that shall include measures for identification, mitigation, disclosure, and monitoring of conflicts, which shall, *inter-alia*, encompass situations where the Electronic Trading Platform Operator or its affiliates, directly or indirectly, participate as Participants;
- (g) make available to its Participants a screen-based trading system for execution or submission of trades on the Electronic Trading Platform;
- (h) put in place a real time surveillance system for monitoring of prices, volumes and positions, to ensure market integrity;
- (i) put in place defined procedures for handling identified surveillance cases, including procedures for investigation, escalation and regulatory reporting;
- (k) make necessary arrangements for its Participants to connect to the Electronic Trading Platform using secure communication channels;
- (l) possess the capability to have a comprehensive network of Participants, and adequate facilities to admit and regulate its Participants;
- (m) put in place a mechanism for redressal of grievances arising out of trades undertaken on the Electronic Trading Platform, in such form and manner as may be specified by the Authority from time to time:
Provided that any dispute arising from or in relation to the settlement of the trade undertaken on the Electronic Trading Platform shall be dealt with in accordance with the applicable laws and Operating Policy;
- (n) have the facility to disseminate information about trades, quantities and quotes in real time;
- (o) employ sufficient number of persons possessing adequate professional and other relevant experience;
- (p) forthwith inform the Competent Authority in writing, in case of any material change in information previously submitted to the Authority; and
- (q) comply with any other requirements as may be specified by the Authority.

11. Participation on the Electronic Trading Platform

(1) Every person, including institutions, whether regulated or unregulated, proprietary trading firms, funds, family offices, and treasury centres shall be eligible to be admitted as a Participant.

Explanation: For the removal of doubts, it is clarified that a person resident in India, in terms of Foreign Exchange Management Act, 1999 (42 of 1999), may also be admitted as a Participant, if such person is

permitted under the provisions of the said Act, or any other law for the time being in force in India, to undertake transactions in Eligible Instruments outside India.

(2) An Electronic Trading Platform Operator shall lay down objective, fair, transparent, and non-discriminatory criteria for admitting a person as a Participant.

(3) Prior to admitting a person as a Participant, an Electronic Trading Platform Operator shall undertake due diligence to ensure that such person:

(a) is of good repute;

(b) has sufficient competence and experience in undertaking transactions on an Electronic Trading Platform; and

(c) has adequate organisational arrangements, including financial and technological resources, appropriate to the nature of its operations.

(4) An Electronic Trading Platform Operator shall uniquely identify its Participants using Legal Entity Identifier, Permanent Account Number (PAN) or any other equivalent document.

12. Products traded on the Electronic Trading Platform

The Electronic Trading Platform Operator shall allow trading on the Electronic Trading Platform in only those Eligible Instruments which are specified under clause (a) of sub-regulation (2) of regulation 5.

13. Operating policy

(1) An Electronic Trading Platform operator shall put in place operating policy, approved by its board which shall be,:

(a) objective, fair, transparent, and non-discriminatory; and

(b) legally binding and enforceable against each Participant.

(2) Such policy shall inter alia include provisions for

(a) onboarding of Participants on the Electronic Trading Platform, as well as their suspension and termination;

(b) roles and responsibilities of the Electronic Trading Platform Operator;

(c) a liability framework for the Participants in the case of breach of the policy;

(d) restrictions or other requirements for using the Electronic Trading Platform;

(e) processing and execution of orders, risk management and control; and

(f) Complaint Redressal and Dispute Resolution Mechanism for participants

(3) Any material change in such policy shall be intimated to the Competent Authority forthwith.

Explanation: For the purposes of this sub-regulation, the expression “material change” shall mean a significant alteration in the procedures, systems, performance standards, or safety requirements, specified in such policy, which affects the ability Electronic Trading Platform Operator to meet its contractual obligations.

(4) An Electronic Trading Platform Operator shall establish and maintain adequate and effective systems and controls, including policies and procedures, to ensure that the Participants comply with such policy.

(5) An Electronic Trading Platform Operator shall promptly address gaps or deficiencies identified in such policy.

(6) An Electronic Trading Platform Operator shall make such policy, including the changes effected thereon, available to the public, *inter alia*, by hosting them on its official website.

14. Risk management

(1) An Electronic Trading Platform Operator shall

(a) lay down sound risk management system and infrastructure for comprehensive management of risks, and ensure that the risks associated with its operations are properly identified and prudently managed;

(b) put in place access control measures for its Participants and take steps to prevent unauthorised access of the Electronic Trading Platform;

(c) have effective systems, controls, and procedures to:

- (i) ensure that its trading systems are resilient, possess adequate capacity to deal with peak order and message volumes, and are able to operate in an orderly manner under conditions of market stress;
 - (ii) reject orders that exceed its pre-determined volume and price thresholds, and to temporarily halt trading of Eligible Instruments traded on its facility where there is a significant price movement in relation to such Eligible Instruments; and
 - (iii) prevent and minimise error trades, promptly identify and rectify such trades where they occur, and determine whether error trades are related to disorderly market activity; and
 - (d) implement and maintain appropriate measures to identify, deter, and prevent Market Abuse on and through its Electronic Trading Platform, and promptly report any incident of Market Abuse to the Authority.
- (2) Where the Electronic Trading Platform Operator permits the Participants to access the Electronic Trading Platform through Algorithmic Trading System, it shall ensure that:
- (a) other Participants on the Electronic Trading Platform are made aware of such access;
 - (b) such access is permitted after the Algorithmic Trading System has been tested to assure that it does not affect the normal operations of the platform; and
 - (c) the personnel deployed by such Participant to operate the Algorithmic Trading System are adequately trained and qualified to operate it.

Clearing and Settlement

15. (1) An Electronic Trading Platform Operator that enables the clearing and settlement of transactions in Eligible Instruments between two or more Participants through its electronic system shall ensure that satisfactory arrangements are in place for securing the timely discharge of the rights and liabilities of the parties to transactions conducted on or through such electronic system and shall inform its Participants of the details of such arrangements and any changes thereto.
- (2) The arrangements referred to in sub-regulation (1) shall be entered into by the Electronic Trading Platform Operator, with an entity, with the prior approval of the Authority.
- Provided that,* if an Electronic Trading Platform operator desirous of offering services of clearing and /or settlement of funds shall, prior to offering such services, seek authorisation as a payment system operator under the International Financial Services Centres Authority (Payment and Settlement Systems) Regulations, 2024.

CHAPTER IV

GENERAL OBLIGATIONS OF AN ELECTRONIC TRADING PLATFORM OPERATOR

16. Business continuity plan and disaster recovery site

An Electronic Trading Platform Operator shall establish and maintain a business continuity plan and a disaster recovery site to maintain data and transaction integrity and ensure the continuity of its operations.

17. Cyber security and cyber resilience

An Electronic Trading Platform Operator shall comply with such cyber security and cyber resilience requirements as may be specified by the Authority from time to time.

18. Appointment of compliance officer

An Electronic Trading Platform Operator shall appoint a compliance officer, who shall be responsible for ensuring compliance with the applicable regulatory requirements.

Chapter V

MISCELLANEOUS

19. Preservation, access and use of data

- (1) An Electronic Trading Platform Operator shall ensure that the confidentiality and security of all data relating to activities on the Electronic Trading Platform is maintained, and access to such data is strictly under its control.
- (2) An Electronic Trading Platform Operator shall maintain all data relating to activities on the Electronic Trading Platform, in a readily retrievable form, for at least eight (8) years:

Provided that the data which may be sought in connection with any investigation by the Authority, shall be maintained for at least three (3) years from the date of completion of such investigation:

Provided further that the data which may be sought in connection with any investigation by any investigative agency, under any law for the time being in force, shall be maintained for such period as prescribed under such law.

(3) In the event of cancellation of the registration by the Authority or surrender of the registration by the Electronic Trading Platform Operator, the Authority may direct the Electronic Trading Platform Operator to share all data relating to activities on the Electronic Trading Platform with the Authority or such other agency as may be specified by the Authority.

20. Returns and reports

(1) An Electronic Trading Platform Operator shall furnish such returns, statements and particulars, in such form and manner as may be specified by the Authority.

(2) Without prejudice to regulation 3, an International Financial Services Centre Banking Unit operating an Electronic Trading Platform shall furnish such returns, statements and particulars, in such form and manner as may be specified by the Authority.

(3) An Electronic Trading Platform Operator shall submit its audited annual financial statements to the Authority within thirty (30) days of their finalisation.

21. Power to call for information

The Authority may, at any time, call for any information, document or record from an Electronic Trading Platform Operator, and such Electronic Trading Platform Operator shall submit the same within the specified time.

22. Inspection, inquiry, investigation, and audit

(1) The Authority may, at any time, undertake inspection or investigation, conduct inquiry or audit of an Electronic Trading Platform Operator.

(2) Every manager, director, managing director, chairperson, officer and other employee of an Electronic Trading Platform Operator shall have the obligation to cooperate with the Authority during the inspection, inquiry, investigation or audit of such ETP Operator.

(3) The Authority may, upon consideration of the report arising out of inspection, inquiry, investigation, or audit of an Electronic Trading Platform Operator, take such action as it may deem fit.

23. Directions by the Authority

Without prejudice to the exercise of its powers under the provisions of the Act and the rules, regulations, or subsidiary instructions issued thereunder, the Authority may, either *suo motu* or on receipt of any information or during pendency or on completion of any inspection, inquiry or investigation, in the interest of public or trade or Participants or the operations of an Electronic Trading Platform, issue such directions as it deems fit.

24. Appointment of auditor by the Authority

The Authority may appoint an auditor to audit the books of account, records, documents, infrastructure, systems, procedures or affairs of an Electronic Trading Platform Operator, in such manner as it may deem fit.

25. Authority to recover the expenses

The Authority shall be entitled to recover from an Electronic Trading Platform Operator such expenses, including the fees paid to the auditors, as may be incurred by it for the purposes of inspecting or investigating the books of account, records, documents, infrastructures, system or procedures of an Electronic Trading Platform Operator.

26. Power to remove difficulties

In order to remove any difficulties in the interpretation or application of the provisions of these regulations, the Authority may issue directions through subsidiary instructions.

27. Power to relax strict enforcement of the regulations

(1) The Authority may, for reasons to be recorded in writing, in the interest of development of financial services market in the International Financial Services Centre, relax the strict enforcement of any requirement of these regulations.

(2) For seeking relaxation under sub-regulation (1), an application giving details and the grounds on which relaxation is being sought shall be filed with the Authority along with a non-refundable fee of USD 1500.

28. Power to specify procedures and issue clarifications

For the purposes of implementation of these regulations and matters incidental thereto, or in order to facilitate and regulate the activities relating to Electronic Trading Platforms, the Authority may specify norms, procedures,

processes, manners, additional requirements, guidelines or provide relaxations, by way of subsidiary instructions and issue such clarifications as may be required.

FIRST SCHEDULE

Eligible Jurisdictions

[see clause (f) of sub-regulation (1) of regulation 2]

No.	Jurisdiction	Authorisation
1.	Singapore	Recognised Market Operator under the Securities and Futures (Organised markets) Regulations, 2018, issued by the Monetary Authority of Singapore.
2.	India	ETP Operator under the Master Direction -Reserve Bank of India (Electronic Trading Platforms) Directions, 2025, issued by the Reserve Bank of India.
3.	United States of America	Alternative trading systems approved under Reg – ATS by the Securities and Exchange Commission.
4.	United Kingdom	Multilateral Trading Facility (MTF) authorised by the Financial Conduct Authority, UK (FCA).
5.	European Union	Multilateral Trading Facility (MTF) authorised and supervised by the National Competent Authority (NCA) of the EU Participant State where the venue is registered and operating under Markets in Financial Instruments Directive II.
6.	Dubai International Financial Centre (DIFC)	An Authorised Market Institution (AMI) in DIFC, authorised to operate an alternative trading system for investments.

SECOND SCHEDULE

Fit and Proper requirements

[see clause (c) of regulation 4]

A person shall be fit and proper if:-

(a) such person has a record of fairness and integrity, including but not limited to:

- (i) financial integrity;
- (ii) good reputation and character; and
- (iii) honesty.

(b) such person has not incurred any of the following disqualifications –

- (i) the person has been convicted by a court for any offence involving moral turpitude or any economic offence or any offence under laws dealing with financial markets and financial institutions;
- (ii) a recovery proceeding has been initiated against the person by a financial regulatory authority and is pending;
- (iii) an order for winding up has been passed against the person for malfeasance;
- (iv) the person has not been declared an undischarged insolvent;
- (v) an order, restraining, prohibiting or debarring the person from accessing, providing or dealing in financial products or financial services, has been passed by any regulatory authority, and a period of three years from the date of the expiry of the period specified in the order has not elapsed;

- (vi) any other order against the person has been passed by the Authority or any other regulatory authority, and a period of three years from the date of the order has not elapsed;
- (vii) the person has been found to be of unsound mind by a court of competent jurisdiction and the finding is in force;
- (viii) the person is financially not sound or has been categorised as a wilful defaulter;
- (ix) the person has been declared a fugitive economic offender; or
- (x) any other disqualification as may be specified by the Authority.

PRAVEEN TRIVEDI, Executive Director

[ADVT.-III/4/Exty./322/2026-27]



भारत का राजपत्र The Gazette of India

सी.जी.-जी.जे.-अ.-05092026-276001
CG-GJ-E-05092026-276001

असाधारण
EXTRAORDINARY

भाग III—खण्ड 4
PART III—Section 4

प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 527]
No. 527]

नई दिल्ली, मंगलवार, सितम्बर 1, 2026/ भाद्र 10, 1948
NEW DELHI, TUESDAY, SEPTEMBER 1, 2026/ BHADRA 10, 1948

अंतरराष्ट्रीय वित्तीय सेवा केंद्र प्राधिकरण

अधिसूचना

गांधीनगर, 25 अगस्त, 2026

अंतरराष्ट्रीय वित्तीय सेवा केंद्र प्राधिकरण (प्रतिभूति बाज़ार में बाज़ार दुरुपयोग का अभिनिषेध) विनियम, 2026

आईएफएससीए/जीएन/2026/012.—भारतीय प्रतिभूति एवं विनियम बोर्ड अधिनियम, 1992 (1992 का 15) की धारा 11 की उप-धारा (2) के खंड (ड) और (छ), और धारा 12 के खंड (क) से (ड) के साथ पठित अंतरराष्ट्रीय वित्तीय सेवा केंद्र प्राधिकरण अधिनियम, 2019 (2019 का 50) की धारा 28 की उप-धारा (1) के साथ पठित धारा 12 और धारा 13 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, अंतरराष्ट्रीय वित्तीय सेवा केंद्र प्राधिकरण, निम्नलिखित विनियम बनाता है, अर्थात:-

अध्याय I

प्रारंभिक

1. संक्षिप्त शीर्षक और प्रारंभ

- (1) इन विनियमों को अंतरराष्ट्रीय वित्तीय सेवा केंद्र प्राधिकरण (प्रतिभूति बाज़ार में बाज़ार दुरुपयोग का अभिनिषेध) विनियम, 2026 कहा जाएगा।
- (2) ये शासकीय राजपत्र में इनके प्रकाशन की तारीख से प्रवृत्त होंगे।

2. उद्देश्य

ये विनियम निवेशकों के हितों की रक्षा के लिए अंतरराष्ट्रीय वित्तीय सेवा केंद्र में प्रतिभूति बाज़ार में बाज़ार दुरुपयोग पर अभिनिषेध का ढांचा विनिर्दिष्ट करते हैं।

3. परिभाषाएं

(1) इन विनियम में, जब तक संदर्भ में कुछ और न कहा गया हो,—

- (क) “अधिनियम” का तात्पर्य अंतरराष्ट्रीय वित्तीय सेवा केंद्र प्राधिकरण अधिनियम, 2019 (2019 का 50) से है;
- (ख) “प्राधिकरण” का तात्पर्य अधिनियम की धारा 4 की उप-धारा (1) के अधीन बनाए गए अंतरराष्ट्रीय वित्तीय सेवा केंद्र प्राधिकरण से है;
- (ग) “संबंधित व्यक्ति” का तात्पर्य ऐसे व्यक्ति से है जो संबंधित कार्य से पहले के छह माह के दौरान किसी एंटिटी से निम्नांकित कारणों से सीधे या अप्रत्यक्ष रूप से, किसी भी तरह से संबद्ध है या रहा है,—
 - (i) अपने अधिकारियों के साथ बार-बार बातचीत;
 - (ii) कोई अनुबंधात्मक, विश्वसनीय या रोजगार संबंध;
 - (iii) निदेशक, अधिकारी या कर्मचारी होना; या
 - (iv) अस्थायी या स्थायी, व्यावसायिक या कारोबारी संबंध सहित कोई पद धारण करना, जो ऐसे व्यक्ति को प्रत्यक्ष या परोक्ष रूप से ऐसी महत्वपूर्ण जानकारी तक पहुँच की अनुमति देता है या जिसे ऐसी जानकारी होने की आशा की जा सकती है, जो जनसाधारण के लिए सुलभ नहीं है;
- (घ) “प्रतिभूतियों में लेन-देन” में निम्नांकित शामिल हैं,—
 - (i) किसी व्यक्ति द्वारा (चाहे वह प्रमुख, एजेंट या मध्यस्थ के रूप में हो, स्वयं या वाहक या फ़र्जी खाते के ज़रिए) किसी भी प्रतिभूतियों के इश्यू के अधीन उन्हें खरीदने, बेचने या अभिदान करने का कार्य करना, या खरीदने, बेचने या अभिदान करने के लिए सहमत होना, या किसी भी तरह से प्रतिभूतियों में लेन-देन करना;
 - (ii) ऐसे कार्य जो जानबूझकर प्रतिभूतियों में निवेशकों के निर्णयों को प्रभावित करने के लिए किए गए हों; और
 - (iii) उपर्युक्त कार्य करने में मदद करना;
- (ङ) “अधिकृत व्यक्ति” का तात्पर्य सूचीबद्ध कंपनी के नियंत्रण शेयरधारक और निदेशक से है, और इसमें वे अन्य व्यक्ति भी शामिल हैं जिन्हें सूचीबद्ध कंपनी इस श्रेणी में रख सकती है;
- (च) “धोखाधड़ी” का तात्पर्य किसी व्यक्ति द्वारा, या उसकी मिलीभगत से किसी अन्य व्यक्ति द्वारा, या उसके एजेंट द्वारा प्रतिभूतियों में लेन-देन करते समय किए गए किसी भी कार्य, अभिव्यक्ति, की गई गलती या उस गलती का संगोपन (चाहे धोखा करने की भावना से हो या नहीं) से है, जिसका उद्देश्य किसी दूसरे व्यक्ति या उसके एजेंट को प्रतिभूतियों में लेन-देन करने के लिए उकसाना हो, चाहे इससे कतिपय सदोष अभिलाभ हुआ हो या हानि से बचने का प्रयास किया गया हो या नहीं, और इनमें निम्नांकित शामिल हैं,—
 - i. सच को जानबूझकर गलत बताना या आवश्यक बात छिपाना ताकि दूसरा व्यक्ति ऐसा कार्य करे जिससे उसे नुकसान हो;
 - ii. किसी ऐसी बात को सच बताना जो सच नहीं है, और जिसे बताने वाला व्यक्ति खुद सच नहीं मानता;
 - iii. किसी ऐसी बात को जानबूझकर छिपाना जिसके बारे में बताने वाले व्यक्ति को जानकारी या विश्वास हो;

- iv. ऐसा वादा करना जिसे पूरा करने का कोई इरादा न हो;
- v. बिना सोचे-समझे या लापरवाही से कोई बात कहना, चाहे वह सच हो या झूठ;
- vi. कोई भी ऐसा कार्य या कार्य न करना जिसे किसी दूसरे कानून में धोखाधड़ी वाला माना गया हो;
- vii. किसी व्यक्ति द्वारा ऐसा धोखा देने वाला व्यवहार जिससे दूसरा व्यक्ति पूरी जानकारी के साथ सहमति न दे पाए या पूरी तरह से शामिल न हो पाए;
- viii. बिना किसी ठोस आधार के कोई झूठी बात कहना;
- ix. प्रतिभूतियाँ जारी करने वाले द्वारा गलत जानकारी देना जिससे प्रतिभूतियों के बाज़ार मूल्य पर प्रभाव पड़े, और निवेशक गुमराह हो जाएं, भले ही उन्होंने उस वक्तव्य या उससे जुड़ी किसी चीज़ पर (बाज़ार मूल्य के अलावा) भरोसा न किया हो,

और "धोखाधड़ी" का तात्पर्य इसी तरह समझा जाएगा।

स्पष्टीकरण.—शंकाओं को दूर करने के लिए, यह स्पष्ट किया जाता है कि इस खंड के दायरे में अच्छे भावना से की गई किसी भी सामान्य टिप्पणी नहीं आती, जो निम्नांकित से जुड़ी हो:—

- i. सरकार की आर्थिक नीति;
 - ii. देश की आर्थिक स्थिति;
 - iii. प्रतिभूति बाज़ार में रुझान; या
 - iv. इसी तरह का कोई अन्य मामला,
- चाहे ऐसी टिप्पणियाँ सार्वजनिक रूप से की गई हों या व्यक्तिगत रूप से;
- (छ) "निकटवर्ती संबंधी" का तात्पर्य किसी व्यक्ति के जीवनसाथी से है और इसमें उस व्यक्ति या जीवनसाथी के माता-पिता, भाई-बहन और बच्चे शामिल हैं, जो या तो आर्थिक रूप से उस व्यक्ति पर निर्भर हैं, या प्रतिभूतियों में ट्रेडिंग से जुड़े निर्णय लेने में उस व्यक्ति से सलाह लेते हैं;
- (ज) "आंतरिक व्यक्ति" का तात्पर्य ऐसे किसी व्यक्ति से है जो,—
- i. संबद्ध व्यक्ति है; या
 - ii. जिसके पास ऐसी आवश्यक जानकारी है जो सार्वजनिक नहीं है;
- (झ) "अंतरराष्ट्रीय वित्तीय सेवा केंद्र" का वही तात्पर्य होगा जो इस अधिनियम की धारा 3 की उप-धारा (1) के खंड (g) में निर्दिष्ट किया गया है;
- (ञ) "सूचीबद्ध" का तात्पर्य अंतरराष्ट्रीय वित्तीय सेवा केंद्र में किसी मान्यता प्राप्त स्टॉक एक्सचेंज पर सूचीबद्ध होने से है;
- (ट) "बाज़ार दुरुपयोग" का तात्पर्य प्रतिभूति बाज़ार में गैर-कानूनी व्यवहार से है, और इसमें आंतरिक व्यक्ति ट्रेडिंग और हेरफेर वाले, धोखाधड़ी वाले और अनुचित व्यापार तौर-तरीके शामिल होंगे, लेकिन यह इन्हीं तक सीमित नहीं होगा;
- (ठ) "आवश्यक गैर-सार्वजनिक जानकारी" या "अप्रकाशित मूल्य संवेदी सूचना" का तात्पर्य किसी एंटीटी या उसकी प्रतिभूतियों से जुड़ी कोई भी जानकारी से है, जो प्रत्यक्ष या परोक्ष रूप से आम तौर पर उपलब्ध नहीं है और जो बिना किसी भेदभाव के जनता के लिए उपलब्ध होने पर, एंटीटी की प्रतिभूतियों के मूल्य पर काफ़ी प्रभाव डाल सकती है, और इसमें आम तौर पर निम्नलिखित से जुड़ी जानकारी शामिल होगी, लेकिन यह इन्हीं तक सीमित नहीं होगी,—
- i. वित्तीय परिणाम;
 - ii. लाभांश;

- iii. पूंजी संरचना में परिवर्तन;
- iv. विलय, विनिवेश, अधिग्रहण, असूचीयन, निपटान और कारोबार का विस्तार, सामान्य कारोबार के दायरे से बाहर के आदेश या अनुबंध मिलना या खत्म होना और ऐसे अन्य लेन-देन;
- v. सेवानिवृत्ति या कार्यकाल समाप्त होने के अतिरिक्त, मुख्य प्रबंधकीय कर्मियों में परिवर्तन, और वैधानिक लेखापरीक्षक या सचिवालयी लेखापरीक्षक का त्यागपत्र;
- vi. 'पर्यावरणीय, सामाजिक और शासन (ईएसजी)' रेटिंग के अतिरिक्त रेटिंग में परिवर्तन;
- vii. निधि जुटाने का प्रस्ताव;
- viii. किसी भी नाम से जाने जाने वाले समझौते, जो एंटीटी के प्रबंधन या नियंत्रण पर प्रभाव डाल सकते हैं;
- ix. ऐसी एंटीटी, उसके प्रवर्तक, निदेशक, मुख्य प्रबंधकीय कर्मियों या सहायक कंपनी द्वारा धोखाधड़ी या व्युतिक्रम, या एंटीटी के मुख्य प्रबंधकीय कर्मियों, प्रवर्तक या निदेशक की गिरफ्तारी, चाहे वह भारत में हुई हो या विदेश में।

स्पष्टीकरण 1.—इस उप-खंड के उद्देश्यों के लिए, "व्युतिक्रम" का तात्पर्य ऋण का भुगतान न करने से है जब वह देय और भुगतान योग्य हो गया हो।

स्पष्टीकरण 2.—प्रवर्तक, निदेशक, मुख्य प्रबंधकीय कर्मियों या सहायक कंपनी द्वारा व्युतिक्रम, यदि यह एंटीटी को प्रभावित करता है, तो उस पर विचार किया जा सकता है।

स्पष्टीकरण 3.—आवर्गी ऋण सुविधाओं के मामले में, यदि देय शेष स्वीकृत की गई सीमा या आहरण शक्ति, इनमें से जो भी कम हो, से लगातार तीस दिनों से अधिक समय तक अधिक रहता है, तो इसे एंटीटी का व्युतिक्रम माना जा सकता है;

- (x) बैंकों/वित्तीय संस्थानों से लिए गए ऋण/उधार के संबंध में समाधान योजना /पुनर्संरचना या एकल-बारगी समाधान;
- (xi) किसी पार्टी/लेनदार द्वारा फ़ाइल की गई समापन याचिका को स्वीकार करना और कारपोरेट देनदार के रूप में एंटीटी के विरुद्ध कारपोरेट दिवाला समाधान प्रक्रिया शुरू करने के लिए कारपोरेट आवेदक या वित्तीय लेनदारों द्वारा अधिकरण में फ़ाइल आवेदन को स्वीकार करना, दिवाला एंड शोधन अक्षमता संहिता, 2016 के अधीन समाधान योजना को स्वीकृति देना या उसे अस्वीकार करना, या किसी विदेशी अधिकार क्षेत्र के कानूनों के अधीन ऐसी ही कोई कार्यवाही करना;
- (xii) वित्तीय विवरण में असत्य जानकारी का पता लगाने, निधि के दुरुपयोग या हेराफेरी या विचलन के लिए एंटीटी या किसी अन्य एंटीटी द्वारा अपराधविज्ञान लेखापरीक्षा (चाहे उसे किसी भी नाम से पुकारा जाए) आरंभ करना और अंतिम अपराधविज्ञान लेखापरीक्षा रिपोर्ट प्राप्त करना;
- (xiii) एंटीटी के संबंध में एंटीटी या उसके निदेशकों, मुख्य प्रबंधकीय कर्मियों, प्रवर्तक या सहायक कंपनी के विरुद्ध भारत या विदेश में किसी नियामक, वैधानिक, प्रवर्तन प्राधिकरण या न्यायिक निकाय द्वारा शुरू की गई कार्रवाई या पारित आदेश;
- (xiv) किसी भी मुकदमे या विवाद का परिणाम जिसका एंटीटी पर प्रभाव पड़ सकता है;
- (xv) सामान्य व्यावसायिक कार्यकाज के अलावा किसी तीसरे पक्ष के लिए गारंटी या क्षतिपूर्ति देना या प्रत्याभूति देना (चाहे उसे किसी भी नाम से पुकारा जाए); या
- (xvi) मुख्य लाइसेंस या नियामक स्वीकृति देना, वापस लेना, अभ्यर्पण करना, निरस्त करना या निलंबित करना;

- (ड) “वाहक/फर्जी खाता” में ब्रोकर लेन-देन के पास रखा गया ट्रेडिंग खाता या अमूर्त खाता या ऐसे ट्रेडिंग खाते से जुड़ा बैंक खाता शामिल है जो किसी व्यक्ति के नाम पर हो, लेकिन जिसे वास्तव में कोई अन्य व्यक्ति नियंत्रित करता हो, चाहे ऐसे खाते में लेन-देन के लिए भुगतान उस अन्य व्यक्ति ने किया हो या नहीं;
 - (ढ) “मान्यता प्राप्त स्टॉक एक्सचेंज” का वही तात्पर्य होगा जो अंतरराष्ट्रीय वित्तीय सेवा केंद्र प्राधिकरण (बाज़ार अवसंरचना संस्थान) विनियम, 2021 के विनियम 2 के उप-विनियम (1) के खंड (थ) के अधीन बताया गया है;
 - (ण) “प्रतिभूतियों” का वही तात्पर्य होगा जो प्रतिभूति अनुबंध (विनियम) अधिनियम, 1956 (1956 का 42) की धारा 2 के खंड (ज) में बताया गया है;
 - (त) “ट्रेडिंग” में किसी भी प्रतिभूति के लिए अभिदान करना, भुनाना, परिवर्तित करना, खरीदना, बेचना, क्रय-विक्रय करना या इनके लिए सहमत होना शामिल है, और “ट्रेड” का तात्पर्य भी इसी तरह से समझा जाएगा।
- (2) इन विनियम में प्रयोग किए गए और परिभाषित न किए गए शब्दों और वाक्यांशों का वही तात्पर्य होगा जो अधिनियम, कंपनी अधिनियम, 2013 (2013 का 18), प्रतिभूति अनुबंध (विनियम) अधिनियम, 1956 (1956 का 42), भारतीय प्रतिभूति विनियम बोर्ड अधिनियम, 1992 (1992 का 15), निक्षेपागार अधिनियम, 1996 (1996 का 22), या इनके अधीन बनाए गए किसी भी नियम या विनियम में दिया गया है, या फिर उनमें किए गए किसी कानूनी परिवर्तन या पुनः लागू किए जाने पर उसका जो तात्पर्य होगा, वही माना जाएगा।

अध्याय II

आंतरिक व्यक्तियों द्वारा सम्प्रेषण और ट्रेडिंग पर अभिनिषेध

4. महत्वपूर्ण गैर-सार्वजनिक जानकारी का सम्प्रेषण या अधिप्राप्ति

- (1) कोई भी आंतरिक व्यक्ति किसी भी व्यक्ति, जिसमें अन्य आंतरिक व्यक्ति भी शामिल हैं, को किसी एंटिटी या सूचीबद्ध या सूचीबद्ध होने वाली प्रतिभूतियों से जुड़ी कोई भी महत्वपूर्ण गैर-सार्वजनिक जानकारी संप्रेषित, प्रदान नहीं करेगा, या उसकी सुलभता की अनुमति नहीं देगा, सिवाय इसके कि ऐसा संवाद सही उद्देश्यों, कर्तव्यों के निर्वहन या कानूनी उत्तरदायित्वों को पूरा करने के लिए किया गया हो।
- स्पष्टीकरण.— इस विनियम के उद्देश्यों के लिए, “सही उद्देश्यों” में किसी आंतरिक व्यक्ति द्वारा साझीदारों, सहयोगियों, ऋणदाताओं, ग्राहकों, आपूर्तिकर्ताओं, शीर्ष प्रबंधकों, बीमाकर्ताओं, विधिक सलाहकारों, लेखापरीक्षकों, दिवाला व्यावसायिकों या दूसरे सलाहकारों या परामर्शदाताओं के साथ कारोबार के सामान्य तरीके में आवश्यक गैर-सार्वजनिक जानकारी शेयर करना शामिल है, जब तक कि ऐसी शेयरिंग इन विनियमों के अधीन निषेध से बचने या उसे दरकिनार करने के लिए न की गई हो।
- (2) कोई भी व्यक्ति किसी आंतरिक व्यक्ति से किसी सूचीबद्ध या सूचीबद्ध होने वाली प्रस्तावित प्रतिभूतियों से जुड़ी आवश्यक गैर-सार्वजनिक जानकारी नहीं लेगा, या उसे संप्रेषित नहीं करवाएगा, सिवाय इसके कि यह सही उद्देश्य, कर्तव्यों का पालन या कानूनी उत्तरदायित्वों को पूरा करने के लिए अनिवार्य हो।
- (3) सही उद्देश्य के लिए आवश्यक गैर-सार्वजनिक जानकारी पाने वाले व्यक्ति को इन विनियमों के लिए “आंतरिक व्यक्ति” माना जाएगा और ऐसा व्यक्ति इन विनियमों के अनुपालन में ऐसी आवश्यक गैर-सार्वजनिक जानकारी की देखरेख करेगा।

5. ट्रेडिंग करना जब उसे महत्वपूर्ण गैर-सार्वजनिक जानकारी उपलब्ध हो

- (1) कोई भी आंतरिक व्यक्ति, जब उसके पास आवश्यक गैर-सार्वजनिक जानकारी हो, ऐसी प्रतिभूतियाँ, जो सूचीबद्ध हैं या सूचीबद्ध होने के लिए प्रस्तावित हैं, में न तो स्वयं ट्रेड करेगा और न ही किसी दूसरे व्यक्ति से ट्रेड करवाएगा।

- (2) जहाँ किसी व्यक्ति ने आवश्यक गैर-सार्वजनिक जानकारी होने पर प्रतिभूतियों में ट्रेड किया है, तो यह माना जाएगा कि ऐसा ट्रेड उसे उपलब्ध ऐसी जानकारी के आधार पर किया गया है।
- (3) यदि किसी व्यक्ति ने आवश्यक गैर-सार्वजनिक जानकारी होने पर भी प्रतिभूतियों में ट्रेड किया है, तो वह अपनी ट्रेडिंग को इन परिस्थितियों को दिखाकर समझा सकता है, जिनमें निम्नांकित शामिल हैं,—
- (क) यह लेन-देन उन आंतरिक व्यक्तियों के मध्य बाज़ार से इतर आंतरिक अंतरण है जिनके पास वही आवश्यक गैर-सार्वजनिक जानकारी थी और उन्होंने विनियम 4 का उल्लंघन नहीं किया है, और दोनों पक्षों ने सोच-समझकर और जानकारी के साथ ट्रेड का निर्णय लिया;
- (ख) यह लेन-देन किसी जाने-माने स्टॉक एक्सचेंज के ब्लॉक लेन-देन विंडो मैकेनिज़्म के माध्यम से उन लोगों के मध्य किया गया, जिनके पास विनियम 4 का उल्लंघन किए बिना आवश्यक गैर-सार्वजनिक जानकारी थी और दोनों पक्षों ने सोच-समझकर और जानकारी के साथ ट्रेड का निर्णय लिया;
- (ग) यह लेन-देन सही था और किसी कानूनी या नियामक उत्तरदायित्व के अधीन किया गया;
- (घ) यह लेन-देन स्टॉक विकल्पों के प्रयोग के अधीन किया गया, जिसके लिए उपयोग का मूल्य प्रभावी कानूनों के अनुपालन से पूर्व तय की गई थी;
- (ङ) गैर-वैयक्तिक आंतरिक व्यक्तियों के मामले में,—
- (i) जिन लोगों के पास ऐसी आवश्यक गैर-सार्वजनिक जानकारी थी, वे ट्रेडिंग के फैसले लेने वाले लोगों से अलग थे और ऐसे फैसले लेने वाले लोगों के पास ऐसी आवश्यक गैर-सार्वजनिक जानकारी नहीं थी जब उन्होंने ट्रेड करने का फैसला लिया; और
- (ii) यह सुनिश्चित करने के लिए सही और पर्याप्त व्यवस्था थी कि इन विनियम का उल्लंघन न हो और जानकारी रखने वाले लोगों ने ट्रेडिंग के निर्णय लेने वाले लोगों को कोई आवश्यक गैर-सार्वजनिक जानकारी नहीं दी और ऐसी व्यवस्थाओं के उल्लंघन का कोई साक्ष्य नहीं है;
- (च) ट्रेड ऐसे अटल ट्रेडिंग प्लान के अधीन किए गए थे जिसे मान्यता प्राप्त स्टॉक एक्सचेंज(जों) को कम से कम एक सौ बीस दिन पहले ही निर्दिष्ट कर दिया गया था।
- 4) प्राधिकरण समय-समय पर ऐसे अतिरिक्त मानक और आवश्यकताएं निर्दिष्ट कर सकता है, जिनमें रिपोर्टिंग की आवश्यकताएं शामिल हैं, जिन्हें वह इन विनियमों के उद्देश्य के लिए आवश्यक समझे।

6. अधिकृत लोगों द्वारा प्रकटीकरण

- (1) हर सूचीबद्ध एंटीटी के पास इस विनियम में बताई गई ज़रूरतों के अनुसार अधिकृत लोगों द्वारा प्रकटीकरण के लिए पॉलिसी होगी।
- (2) हर अधिकृत व्यक्ति, सूचीबद्ध एंटीटी को उन विनिर्दिष्ट प्रतिभूतियों की संख्या बताएगा जो उसने या उसके निकटवर्ती संबंधियों ने ऐसे लेन-देन के दो ट्रेडिंग दिनों के भीतर खरीदी या बेची हैं, यदि किसी कैलेंडर तिमाही में, चाहे एक लेन-देन में या लेन-देन की सीरीज़ में ट्रेड की गई विनिर्दिष्ट प्रतिभूतियों का मूल्य की यूएसडी 25 हजार से अधिक या प्राधिकरण द्वारा बताए गए किसी अन्य मूल्य से अधिक हो।

स्पष्टीकरण 1.— इस उप-विनियम के उद्देश्य के लिए, “विनिर्दिष्ट प्रतिभूतियाँ” शब्द में सूचीबद्ध एंटीटी की इक्विटी लिखते, ऋण प्रतिभूतियाँ और कोई भी अन्य व्युत्पन्न लिखते शामिल होंगी।

स्पष्टीकरण 2.— “इक्विटी लिखत” शब्द का तात्पर्य सूचीबद्ध एंटीटी द्वारा जारी किए गए इक्विटी शेयर, परिवर्तनीय डिबेंचर, अधिमान शेयर और शेयर वारंट से है।

- (3) कंपनी को उप-विनियम (2) के अधीन, प्रकटीकरण प्राप्त होने के दो कार्य दिवसों के भीतर सूचीबद्ध एंटीटी, उस जानकारी के बारे में मान्यता प्राप्त स्टॉक एक्सचेंज (जहाँ उसके शेयर सूचीबद्ध हैं) को सूचित करना होगा और उस जानकारी को अपनी वेबसाइट पर भी डालना होगा।

अध्याय III

छलकपट, धोखाधड़ी और अनुचित ट्रेड प्रथाओं पर अभिनिषेध

7. प्रतिभूतियों में कतिपय लेन-देन पर अभिनिषेध।

कोई भी व्यक्ति प्रत्यक्ष या परोक्ष ढंग से,—

- (क) धोखाधड़ी तरीके से प्रतिभूतियों का न तो क्रय-विक्रय करेगा और न ही अन्यथा लेन-देन करेगा;
- (ख) सूचीबद्ध या सूचीबद्ध होने का प्रस्ताव वाली प्रतिभूतियों की ट्रेडिंग के संबंध में, अधिनियम, भारतीय प्रतिभूति और विनियम बोर्ड अधिनियम, 1992 (1992 का 15), या उसके अधीन जारी नियमों या विनियम के उपबंध का उल्लंघन करते हुए कोई छलकपटपूर्ण या धोखा देने वाले डिवाइस या तरकीब का प्रयोग नहीं करेगा;
- (ग) सूचीबद्ध या सूचीबद्ध होने हेतु प्रस्तावित प्रतिभूतियों में लेन-देन करने या जारी करने के संबंध में धोखा देने के लिए कोई डिवाइस, योजना या छलकपट का प्रयोग नहीं करेगा; या
- (घ) किसी ऐसे कार्य, प्रैक्टिस, या व्यापार में शामिल होना जो किसी व्यक्ति के साथ छल या धोखा करता है या करेगा, ऐसी प्रतिभूतियों की किसी भी लेन-देन या इश्यू के संबंध में जो अधिनियम, भारतीय प्रतिभूति एवं विनियम बोर्ड अधिनियम, 1992 (1992 का 15), या उसके अधीन जारी नियमों या विनियमों के उपबंध का उल्लंघन करके सूचीबद्ध हैं या सूचीबद्ध होने हेतु प्रस्तावित हैं।

8. छलकपट, धोखाधड़ी और अनुचित ट्रेड प्रथाओं पर अभिनिषेध

- (1) विनियम 7 पर कोई बुरा प्रभाव डाले बिना, कोई भी व्यक्ति प्रतिभूति बाज़ार में छलकपट, धोखाधड़ी और अनुचित ट्रेड प्रथाओं में शामिल नहीं होगा।
- (2) प्रतिभूतियों में लेन-देन को छलकपट, धोखाधड़ी और अनुचित ट्रेड प्रथा माना जाएगा यदि इसमें नीचे दिए गए में से कोई भी शामिल हो,—
 - (क) जानबूझकर ऐसे कार्य में शामिल होना जिससे प्रतिभूति बाज़ार में ट्रेडिंग का झूठा या गुमराह करने वाला दिखावा हो;
 - (ख) ऐसी प्रतिभूतियों में लेन-देन करना जिसका उद्देश्य लाभप्रद स्वामित्व का अंतरण न हो, बल्कि सिर्फ़ गलत लाभ या हानि से बचने के लिए ऐसी प्रतिभूतियों का मूल्य बढ़ाने, कम करने या उसमें उतार-चढ़ाव लाने के तरीके के तौर पर कार्य करना हो;
 - (ग) किसी भी व्यक्ति को प्रतिभूतियों के किसी इश्यू में अभिदान करने के लिए उकसाना, ताकि इसके लिए किसी अन्य व्यक्ति को कोई पैसा अग्रिम रूप से देकर या अग्रिम देने के लिए राज़ी होकर या किसी और तरीके से धोखाधड़ी से प्रतिभूतियों के ऐसे इश्यू के लिए न्यूनतम अभिदान प्राप्त किया जा सके;
 - (घ) किसी भी व्यक्ति को प्रतिभूतियों में लेन-देन करने के लिए उकसाना ताकि किसी भी तरीके से प्रतिभूतियों के मूल्य में बनावटी तौर पर बढोतरी हो, कम हो, बनी रहे या उतार-चढ़ाव हो, जिसमें किसी व्यक्ति को सीधे या इनडायरेक्ट तरीके से कोई पैसा या पैसे की कीमत देना, ऑफ़र करना या पेमेंट करने या ऑफ़र करने के लिए राज़ी होना शामिल है;
 - (ङ) प्रतिभूतियों के मूल्य में हेरफेर करने वाला कोई भी कार्य या चूक, जिसमें प्रतिभूतियों के संदर्भ मूल्य या बेंचमार्क मूल्य को प्रभावित करना या उसमें हेरफेर करना शामिल है;
 - (च) प्रतिभूतियों में कार्य करने वाले व्यक्ति द्वारा जानबूझकर प्रतिभूतियों से संबंधित कोई भी जानकारी प्रकाशित करना या करवाना या रिपोर्ट करना या करवाना, जिसमें वित्तीय परिणाम, वित्तीय विवरण, विलय और अधिग्रहण, नियामक स्वीकृतियां शामिल हैं, जो सत्य नहीं हैं, या जिसके बारे में वह प्रतिभूतियों में कार्य करने से पहले या उसके दौरान सत्य होने का भरोसा नहीं करता है;

- (छ) इसे निष्पादित करने के इरादे के बिना या ऐसी प्रतिभूति के स्वामित्व में परिवर्तन के इरादे के बिना प्रतिभूतियों में लेनदेन करना;
- (ज) चोरी की गई, नकली या धोखाधड़ी से जारी की गई प्रतिभूतियों, चाहे वे भौतिक या अमूर्त हों, को बेचना, उनमें ट्रेड करना या गिरवी रखना:
- बशर्ते कि चोरी की, नकली या धोखाधड़ी से जारी की गई ऐसी प्रतिभूतियों को बेचना, उनमें ट्रेड करना या गिरवी रखना, छलकपट, धोखाधड़ी, या अनुचित ट्रेड नहीं माना जाएगा, यदि,—
- (i) चोरी की गई, नकली या धोखाधड़ी से जारी की गई प्रतिभूतियों को बेचने, उनमें ट्रेड करने या गिरवी रखने वाला व्यक्ति समय के साथ साथ धारक बन गया हो; या
- (ii) चोरी की गई, नकली या धोखाधड़ी से जारी की गई प्रतिभूतियों का पहले किसी असली लेन-देन के माध्यम से बाज़ार में ट्रेड किया गया हो;
- (झ) किसी भी मीडिया, चाहे वह भौतिक हो या डिजिटल, के माध्यम से ऐसी जानकारी या सलाह फैलाना, जिसके बारे में फैलाने वाले को पता हो कि वह झूठी या गुमराह करने वाली है और जो प्रतिभूतियों में लेन-देन करने वाले निवेशकों के निर्णय पर प्रभाव डालने के लिए बनाई गई है, या ऐसा होने की संभावना है;
- (ञ) कोई बाज़ार प्रतिभागी ग्राहक की जानकारी या ग्राहक के निदेशों के बिना उसकी ओर से लेन-देन करता है या ग्राहक की निधि या प्रतिभूतियों का दुरुपयोग करता है या उन्हें अन्य स्थान पर लगाता है, जो न्यासी क्षमता में रखे गए हैं;
- (ट) किसी भी प्रतिभूतियों के संबंध में परिपत्र लेन-देन में शामिल होना ताकि ऐसी प्रतिभूतियों में ट्रेडिंग का बनावटी दिखावा किया जा सके या ऐसी प्रतिभूतियों के मूल्य को बढ़ाया, घटाया या उसमें उतार-चढ़ाव लाया जा सके;
- (ठ) किसी बाज़ार प्रतिभागी द्वारा किसी व्यक्ति को अपनी ब्रोकरेज या कमीशन या आय बढ़ाने के उद्देश्य से प्रतिभूतियों में लेन-देन करने के लिए धोखाधड़ी से उकसाना;
- (ड) प्रतिभूति बाज़ार में किसी भी कार्यकलाप से जुड़े अनुबंध नोट्स, ग्राहक अनुदेश, प्रतिभूति शेष विवरण, या ग्राहक खाता विवरण जैसे रिकॉर्ड को पहले से बनाना या गलत ढंग से बनाना;
- (ढ) किसी व्यक्ति द्वारा प्रतिभूतियों में दिया गया कोई भी आदेश, जबकि उसके पास उन प्रतिभूतियों, उनकी अंतरनिहित प्रतिभूतियों या उसके व्युत्पन्न में होने वाले किसी बड़े लेन-देन के बारे में प्रत्यक्ष या परोक्ष रूप में ऐसी जानकारी हो जो सार्वजनिक रूप में उपलब्ध न हो;
- (ण) जानबूझकर झूठी या गुमराह करने वाली खबरें डालना जिससे प्रतिभूतियों की बिक्री या खरीद प्रभावित हो सकती है;
- (त) प्रतिभूतियों या प्रतिभूति बाज़ार से जुड़ी सेवाओं की गलत तरीके से बिक्री;
- स्पष्टीकरण.—इस खंड के उद्देश्य से, “गलत तरीके से बिक्री” का तात्पर्य किसी व्यक्ति द्वारा, प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से, प्रतिभूतियों या प्रतिभूति बाज़ार से जुड़ी सेवाओं की बिक्री करना, जिसके अधीन:—
- (i) जानबूझकर गलत या गुमराह करने वाला बयान देना;
- (ii) जानबूझकर आवश्यक तथ्यों को छिपाना या न बताना;
- (iii) जानबूझकर उससे जुड़े जोखिम को छिपाना; या
- (iv) खरीदार के लिए प्रतिभूतियों या सेवा की उपयुक्तता सुनिश्चित करने के लिए उचित सावधानी न बरतना।
- (थ) प्रतिभूतियों की बनावटी मांग या मूल्य बनाना;
- (द) ट्रेडिंग गतिविधि को बनावटी रूप से बढ़ाने के लिए एक ही कीमत पर प्रतिभूतियों खरीदना और बेचना;
- (ध) ऐसी अफवाह फैलाना या गुमराह करने वाले कार्यकलाप करना जिससे प्रतिभूतियों के मूल्य ऊपर या नीचे जा सके;

- (न) आदेश को पूरा करने के इरादे के बिना बार-बार आदेश देना और उसे निरस्त करना, ताकि केवल आपूर्ति या मांग में परिवर्तन करके प्रतिभूतियों की मांग और मूल्य को बनावटी रूप से तय किया जा सके;
 - (प) किसी इकाई की संपत्ति या कमाई का कोई भी विचलन, दुरुपयोग या हेराफेरी करना, जिससे प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से उसकी प्रतिभूतियों के मूल्य में हेरफेर हो;
 - (फ) इकाई के खाता बहियों या वित्तीय विवरण में हेरफेर करना, जिससे प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से उसकी प्रतिभूतियों के मूल्य में हेरफेर हो; या
 - (ब) किसी व्यक्ति द्वारा किसी सामूहिक निवेश योजना को प्रत्यायोजित करके या प्रत्यायोजित करवाकर या चलाकर या चलवाकर गैर-कानूनी तरीके से निधि जुटाना;
- स्पष्टीकरण.—शंकाओं को दूर करने के लिए, यह स्पष्ट किया जाता है कि इस उप-विनियम में निर्दिष्ट कृत्य और व्युत्क्रम ही अंतिम नहीं हैं, और यदि कोई कृत्य या चूक विनियम 7 के दायरे में आती है तो वह प्रतिबंधित है, भले ही वह इस उप-विनियम में शामिल न हो या इस उप-विनियम में उसे केवल किसी खास श्रेणी के व्यक्ति (व्यक्तियों) द्वारा किए जाने या न किए जाने के तौर पर निर्दिष्ट किया गया हो।

अध्याय IV

विविध

9. बाज़ार दुरुपयोग का अभिनिषेध करने के लिए संस्थागत व्यवस्था।

- (1) प्रत्येक सूचीबद्ध कंपनी को बाज़ार दुरुपयोग के अभिनिषेध के लिए इन नियमों का पालन सुनिश्चित करने हेतु आंतरिक नियंत्रण की पर्याप्त और प्रभावी प्रणाली और आचार संहिता लागू करनी होगी।
- (2) आंतरिक नियंत्रण में, अन्य बातों के अतिरिक्त, निम्नलिखित उपबंध शामिल होंगे:—
 - (क) महत्वपूर्ण गैर-सार्वजनिक जानकारी की पहचान करना और उसकी गोपनीयता बनाए रखना;
 - (ख) महत्वपूर्ण गैर-सार्वजनिक जानकारी प्राप्त करने और उसे साझा करने पर उचित प्रतिबंध लगाना;
 - (ग) उन कर्मचारियों की पहचान करना जिनकी महत्वपूर्ण गैर-सार्वजनिक जानकारी तक पहुँच है; और
 - (घ) नियंत्रण की प्रभावशीलता का मूल्यांकन करने के लिए समय-समय पर उनकी समीक्षा करना।
- (3) प्राधिकरण उप-नियम (1) और (2) पर प्रतिकूल प्रभाव डाले बिना, आंतरिक नियंत्रण और आचार संहिता के लिए यथोचित अतिरिक्त मानक तय कर सकता है।

10. नियमों के उल्लंघन पर कार्रवाई

प्राधिकरण इन नियमों के किसी भी उल्लंघन से अधिनियम के संबंधित उपबंधों के अनुसार निपटेगा।

11. रजिस्ट्रीकरण का निलंबन या निरस्तीकरण

प्राधिकरण, अधिनियम या उसके अधीन बने नियमों के संबंधित उपबंधों के अधीन किसी भी कार्रवाई पर प्रतिकूल प्रभाव डाले बिना, लिखित रूप में दर्ज कारणों से और निवेशकों तथा प्रतिभूति बाज़ार के हित में, इन नियमों के उपबंधों के उल्लंघन के लिए प्राधिकरण द्वारा विनियमित किसी व्यक्ति के विरुद्ध निम्नलिखित में से कोई भी कार्रवाई कर सकता है:—

- (क) चेतावनी या निंदा जारी करना; या
- (ख) ऐसे व्यक्ति का रजिस्ट्रीकरण निलंबित या निरस्त करना।

12. कठिनाइयों को दूर करने की शक्ति।

प्राधिकरण इन नियमों के उपबंधों की व्याख्या या लागू करने में किसी भी कठिनाई को दूर करने के लिए, सहायक निदेशों के माध्यम से निदेश या स्पष्टीकरण जारी कर सकता है।

13. नियम, प्रक्रियाएं तय करने और स्पष्टीकरण जारी करने की शक्ति

प्राधिकरण इन नियमों को लागू करने और उससे जुड़े मामलों के लिए, सहायक निदेशों के माध्यम से नियम, प्रक्रियाएं, विधियां या कोई अतिरिक्त आवश्यकताएं तय कर सकता है, और आवश्यकतानुसार स्पष्टीकरण जारी कर सकता है।

14. नियमों के कड़े पालन में ढील देने की शक्ति

- (1) प्राधिकरण, लिखित रूप में दर्ज कारणों से, अंतरराष्ट्रीय वित्तीय सेवा केंद्र में वित्तीय सेवा बाज़ार के विकास के हित में, इन नियमों की किसी भी आवश्यकता के कड़े पालन में ढील दे सकती है।
- (2) उप-विनियम (1) के अधीन छूट पाने के लिए, प्राधिकरण के पास आवेदन प्रस्तुत करना होगा। इस आवेदन में छूट मांगने के कारण और पूरी जानकारी देनी होगी, साथ ही प्राधिकरण द्वारा निर्धारित अप्रतिदेय शुल्क भी जमा कराना होगा।
- (3) प्राधिकरण, उप-विनियम (2) के अधीन प्रस्तुत आवेदन (जिसमें मांगी गई पूर्ण जानकारी का जवाब भी शामिल हो) मिलने के साठ दिनों के भीतर उस पर कार्रवाई करेगा। साथ ही, आवेदक द्वारा मांगी गई छूट को स्वीकृत या अस्वीकृत करने के कारणों को भी दर्ज करेगा।

15. अप्रयोज्यता और संरक्षण

- (1) इन विनियम के लागू होने की तारीख से, अंतरराष्ट्रीय वित्तीय सेवा केंद्र में 'भारतीय प्रतिभूति एवं विनियम बोर्ड (आंतरिक व्यक्ति ट्रेडिंग पर अभिनिषेध) विनियम, 2015' और 'भारतीय प्रतिभूति एवं विनियम बोर्ड (प्रतिभूति बाज़ार से सम्बद्ध धोखाधड़ी और अनुचित व्यापार तौर-तरीकों पर अभिनिषेध) विनियम, 2003' लागू नहीं होंगे।
- (2) उप-विनियम (1) में दी गई किसी भी बात के बावजूद, इन विनियम के लागू होने से पहले उप-विनियम (1) में निर्दिष्ट विनियम के अधीन किया गया कोई भी कार्य या की गई कोई भी कार्रवाई, इन विनियमों के संबंधित उपबध्दों के अधीन की गई या ली गई कार्रवाई माना जाएगा।

प्रदीप रामकृष्णन, कार्यकारी निदेशक

[विज्ञापन-III/4/असा./295/2026-27]

INTERNATIONAL FINANCIAL SERVICES CENTRES AUTHORITY

NOTIFICATION

Gandhinagar, the 25th August, 2026

International Financial Services Centres Authority (Prohibition of Market Abuse in Securities Markets) Regulations, 2026.

IFSCA/GN/2026/012.— In exercise of the powers conferred by section 12 and section 13 read with sub-section (1) of section 28 of the International Financial Services Centres Authority Act, 2019 (50 of 2019), read with clauses I and (g) of sub-section (2) of section 11, and clauses (a) to I of section 12A of the Securities and Exchange Board of India Act, 1992 (15 of 1992), the International Financial Services Centres Authority hereby makes the following Regulations, namely:-

CHAPTER I

PRELIMINARY

1. Short title and commencement.

- (1) These Regulations may be called the International Financial Services Centres Authority (Prohibition of Market Abuse in Securities Markets) Regulations, 2026.
- (2) They shall come into force on the date of their publication in the Official Gazette.

2. Objective.

These Regulations specify the framework for prohibiting market abuse in the securities market in the International Financial Services Centre, in order to protect the interests of investors.

3. Definitions.

(1) In these Regulations, unless the context otherwise requires,—

- (a) “Act” means the International Financial Services Centres Authority Act, 2019 (50 of 2019);
- (b) “Authority” means the International Financial Services Centres Authority established under sub-section (1) of section 4 of the Act;
- (c) “connected person” means a person who is or has been, during the six months prior to the concerned act, associated with an entity, directly or indirectly, in any capacity, including by reason of,—
 - (i) frequent communication with its officers;
 - (ii) any contractual, fiduciary or employment relationship;
 - (iii) being a director, officer or an employee ; or
 - (iv) holding any position, including a professional or business relationship, whether temporary or permanent, that allows or is reasonably expected to allow such person, directly or indirectly, access to material non-public information;
- (d) “dealing in securities” includes,—
 - (i) an act of buying, selling or subscribing pursuant to any issue of any securities or agreeing to buy, sell or subscribe to any issue of any securities or otherwise transacting in any way in any securities by any person, including as principal, agent, or intermediary, either by themselves or through mule accounts;
 - (ii) acts which may be knowingly designed to influence the decision of investors in securities; and
 - (iii) an act of providing assistance to carry out the aforementioned acts;
- (e) “designated person” means the controlling shareholders and directors of a listed entity, and includes such other persons who may be categorised as such by the listed entity;
- (f) “fraud” means any act, expression, omission or concealment committed, whether in a deceitful manner or not, by a person, by any other person with his connivance, or by his agent while dealing in securities, in order to induce another person or his agent to deal in securities, whether or not there is any wrongful gain or avoidance of any loss, and includes,—
 - (i) a knowing misrepresentation of the truth or concealment of material fact in order that another person may act to his detriment;
 - (ii) a suggestion, as a fact, of that which is not true, which such person does not believe it to be true;
 - (iii) an active concealment of a fact by such person having knowledge or belief of the fact;
 - (iv) a promise made without any intention of performing it;
 - (v) a representation made in a reckless and careless manner whether it be true or false;
 - (vi) any act or omission specifically declared to be fraudulent by any other law;
 - (vii) deceptive behaviour by such person depriving another of informed consent or full participation;
 - (viii) a false statement made without reasonable ground for believing it to be true;
 - (ix) the act of an issuer of securities giving out misinformation that affects the market price of the securities, resulting in investors being misled even though they did not rely on the statement itself or anything derived from it other than the market price,

and “fraudulent” shall be construed accordingly.

Explanation.—For the removal of doubts, it is clarified that the scope of this clause shall not extend to any general comment made in good faith regarding:—

- (i) the economic policy of a government;
- (ii) the economic situation of a country;
- (iii) trends in the securities markets; or

- (iv) any other matter of a like nature,
irrespective of whether such comments are made in public or in private;
- (g) “immediate relative” means spouse of a person and includes parent, sibling, and child of such person or of the spouse, any of whom is either dependent financially on such person, or consults such person in taking decisions relating to trading in securities;
- (h) “insider” means any person who is,—
 - (i) a connected person; or
 - (ii) in possession of, or having access to, material non-public information;
- (i) “International Financial Services Centre” shall have the same meaning as assigned to it under clause (g) of sub-section (1) of section 3 of the Act;
- (j) “listed” means listed on a recognised stock exchange in the International Financial Services Centre;
- (k) “market abuse” means unlawful behaviour in the securities market, and shall include, but not be restricted to, insider trading and manipulative, fraudulent and unfair trade practice;
- (l) “material non-public information” or “unpublished price sensitive information” means any information, relating to an entity or its securities, directly or indirectly, which is not generally available and which upon becoming generally available to the public on a non-discriminatory basis, is likely to materially impact the price of the securities of the entity, and shall ordinarily include, but not be restricted to, information relating to the following,—
 - (i) financial results;
 - (ii) dividends;
 - (iii) change in capital structure;
 - (iv) mergers, de-mergers, acquisitions, delistings, disposals and expansion of business, award or termination of orders or contracts not in the normal course of business and such other transactions;
 - (v) changes in key managerial personnel, other than due to superannuation or end of term, and resignation of a statutory auditor or secretarial auditor;
 - (vi) change in rating(s), other than ‘Environmental, Social and Governance (ESG)’ rating(s);
 - (vii) fund raising proposed to be undertaken;
 - (viii) agreements, by whatever name called, which may impact the management or control of the entity;
 - (ix) fraud or default by such entity, its promoter, director, key managerial personnel or subsidiary, or arrest of key managerial personnel, promoter or director of the entity, whether occurred within India or abroad.

Explanation 1.— For the purposes of this sub-clause, “default” shall mean non-payment of debt when it has become due and payable.

Explanation 2.— Default by a promoter, director, key managerial personnel or subsidiary may be considered, if it impacts the entity.

Explanation 3.— Default in case of revolving credit facilities, by the entity, may be considered if the outstanding balance remains continuously in excess of the sanctioned limit or drawing power, whichever is lower, for more than thirty days;
- (x) resolution plan/ restructuring or one-time settlement in relation to loans/borrowings from banks/financial institutions;
- (xi) admission of winding-up petition filed by any party/ creditors and admission of application by the Tribunal filed by the corporate applicant or financial creditors for initiation of corporate insolvency resolution process against the entity as a corporate debtor, approval of resolution plan or rejection thereof under the Insolvency and Bankruptcy Code, 2016, or any similar proceedings under the laws of any foreign jurisdiction;

- (xii) initiation of forensic audit, by whatever name called, by the entity or any other entity for detecting mis-statement in financials, misappropriation or siphoning or diversion of funds and receipt of final forensic audit report;
- (xiii) action(s) initiated or orders passed within India or abroad, by any regulatory, statutory, enforcement authority or judicial body against the entity or its directors, key managerial personnel, promoter or subsidiary, in relation to the entity;
- (xiv) outcome of any litigation(s) or dispute(s) which may have an impact on the entity;
- (xv) giving of guarantees or indemnity or becoming a surety, by whatever name called, for any third party, by the entity not in the normal course of business; or
- (xvi) grant, withdrawal, surrender, cancellation or suspension of key licenses or regulatory approvals;
- (m) “mule account” includes a trading account maintained with a broker dealer or a dematerialised account or bank account linked with such trading account in the name(s) of a person, where the account is effectively controlled by another person, whether or not the consideration for transactions in such account is paid by such other person;
- (n) “recognised stock exchange” shall have the same meaning as assigned to it under clause (q) of sub-regulation (1) of regulation 2 of the International Financial Services Centres Authority (Market Infrastructure Institutions) Regulations, 2021;
- (o) “securities” shall have the meaning assigned to it under clause (h) of section 2 of the Securities Contracts (Regulation) Act, 1956 (42 of 1956);
- (p) “trading” includes subscribing, redeeming, switching, buying, selling, dealing, or agreeing to subscribe, redeem, switch, buy, sell, deal in any securities, and “trade” shall be construed accordingly.
- (2) Words and expressions used and not defined in these Regulations but defined in the Act, the Companies Act, 2013 (18 of 2013), the Securities Contracts (Regulation) Act, 1956 (42 of 1956), the Securities and Exchange Board of India Act, 1992 (15 of 1992), the Depositories Act, 1996 (22 of 1996), or any rules or regulations made thereunder shall have the same meanings as respectively assigned to them in those Acts, rules or regulations made thereunder or any statutory modification or re-enactment thereto, as the case may be.

CHAPTER II

RESTRICTIONS ON COMMUNICATION AND TRADING BY INSIDERS

4. Communication or procurement of material non-public information.

- (1) No insider shall communicate, provide or allow access to any material non-public information relating to an entity or securities listed or proposed to be listed to any person, including other insiders, except where such communication is in furtherance of legitimate purposes, performance of duties or discharge of legal obligations.

Explanation.— For the purposes of this regulation, the expression “legitimate purposes” includes sharing of material non-public information in the ordinary course of business by an insider with partners, collaborators, lenders, customers, suppliers, lead managers, underwriters, legal advisors, auditors, insolvency professionals or other advisors or consultants, so long as such sharing is not undertaken to evade or circumvent the prohibitions under these Regulations.

- (2) No person shall procure from, or cause the communication by, any insider of material non-public information, relating to an entity or securities listed or proposed to be listed, except in furtherance of legitimate purposes, performance of duties or discharge of legal obligations.
- (3) A person in receipt of material non-public information pursuant to legitimate purposes shall be considered an “insider” for the purposes of these Regulations and such person shall handle such material non-public information in compliance with these Regulations.

5. Trading when in possession of material non-public information.

- (1) No insider shall trade or cause any other person to trade in securities that are listed or proposed to be listed, when in possession of material non-public information.
- (2) Where a person has traded in securities while being in possession of material non-public information, it shall be presumed that such trade(s) were executed on the basis of such information possessed by him.

- (3) Where a person has traded in securities while in possession of material non-public information, he may explain his trading by demonstrating the circumstances, including the following,—
- (a) the transaction is an off-market inter-se transfer between insiders who were in possession of the same material non-public information without being in breach of regulation 4, and both parties had made a conscious and informed trade decision;
 - (b) the transaction was carried out through the block deal window mechanism of a recognised stock exchange, between persons who were in possession of the material non-public information without being in breach of regulation 4 and both parties had made a conscious and informed trade decision;
 - (c) the transaction was bona fide and carried out pursuant to a statutory or regulatory obligation;
 - (d) the transaction was undertaken pursuant to the exercise of stock options in respect of which the exercise price was pre-determined in compliance with the applicable laws;
 - (e) in the case of non-individual insiders,—
 - (i) the individuals who were in possession of such material non-public information were different from the individuals taking trading decisions and such decision-making individuals were not in possession of such material non-public information when they took the decision to trade; and
 - (ii) appropriate and adequate arrangements were in place to ensure that these Regulations are not violated and no material non-public information was communicated by the individuals possessing the information to the individuals taking trading decisions and there is no evidence of such arrangements having been breached;
 - (f) trades were pursuant to an irrevocable trading plan already disclosed to the recognised stock exchange(s) at least one hundred and twenty days in advance.
- (4) The Authority may specify such additional standards and requirements, including reporting requirements, from time to time, as it may deem necessary for the purpose of these Regulations.

6. Disclosure by designated persons.

- (1) Every listed entity shall have a policy for disclosures by designated persons in accordance with the requirements specified in this regulation.
- (2) Every designated person shall disclose to the listed entity the number of specified securities acquired or disposed of by him or his immediate relatives, within two trading days of such transaction, if the value of the specified securities traded, whether in one transaction or in a series of transactions, over any calendar quarter, aggregates to a traded value in excess of USD twenty-five thousand or such other value as may be specified by the Authority.

Explanation 1.— For the purposes of this sub-regulation, the term “specified securities” shall include equity instruments, debt securities, and any other derivative instruments of the listed entity.

Explanation 2.— The term “equity instruments” means equity shares, convertible debentures, preference shares and share warrants issued by the listed entity.

- (3) The listed entity shall, within two working days of receipt of the disclosure under sub-regulation (2), notify such information to the recognised stock exchange(s) where its securities are listed, and also host such disclosure on its website.

CHAPTER III

PROHIBITION OF MANIPULATIVE, FRAUDULENT AND UNFAIR TRADE PRACTICES

7. Prohibition of certain dealings in securities.

No person shall directly or indirectly,—

- (a) buy, sell or otherwise deal in securities in a fraudulent manner;
- (b) use or employ, any manipulative or deceptive device or contrivance in contravention of the provisions of the Act, the Securities and Exchange Board of India Act, 1992 (15 of 1992), or the rules or regulations issued thereunder, in relation to trading of securities listed or proposed to be listed;

- (c) employ any device, scheme or artifice to defraud in connection with dealing in or issue of securities which are listed or proposed to be listed; or
- (d) engage in any act, practice, or course of business which operates or would operate as fraud or deceit upon any person in connection with any dealing in or issue of securities which are listed or proposed to be listed in contravention of the provisions of the Act, the Securities and Exchange Board of India Act, 1992 (15 of 1992), or the rules or regulations issued thereunder.

8. Prohibition of manipulative, fraudulent and unfair trade practices.

- (1) Without prejudice to regulation 7, no person shall indulge in a manipulative, fraudulent or unfair trade practice in the securities market.
 - (2) Dealing in securities shall be deemed to be manipulative, fraudulent or unfair trade practice if it involves any of the following,—
 - (a) knowingly indulging in an act which creates false or misleading appearance of trading in the securities market;
 - (b) dealing in securities not intended to effect transfer of beneficial ownership but intended to operate only as a device to inflate, depress or cause fluctuations in the price of such securities for wrongful gain or avoidance of loss;
 - (c) inducing any person to subscribe to an issue of securities for fraudulently securing the minimum subscription to such issue of securities, by advancing or agreeing to advance any money to any other person or through any other means;
 - (d) inducing any person for dealing in securities for artificially inflating, depressing, maintaining or causing fluctuation in the price of securities through any means including by paying, offering or agreeing to pay or offer any money or money's worth, directly or indirectly, to any person;
 - (e) any act or omission amounting to manipulation of the price of securities including influencing or manipulating the reference price or benchmark price of securities;
 - (f) knowingly publishing or causing to publish or reporting or causing to report by a person dealing in securities any information relating to securities, including financial results, financial statements, mergers and acquisitions, regulatory approvals, which is not true, or which he does not believe to be true prior to or in the course of dealing in securities;
 - (g) entering into a transaction in securities without intention of performing it or without intention of change of ownership of such security;
 - (h) selling, dealing in or pledging of stolen, counterfeit or fraudulently issued securities whether in physical or dematerialised form:

Provided that such selling, dealing in or pledging of stolen, counterfeit or fraudulently issued securities shall not be considered as a manipulative, fraudulent, or unfair trade practice if,—

 - (i) the person selling, dealing in or pledging stolen, counterfeit or fraudulently issued securities was a holder in due course; or
 - (ii) the stolen, counterfeit or fraudulently issued securities were previously traded on the market through a bona fide transaction;
 - (i) disseminating information or advice through any media, whether physical or digital, which the disseminator knows to be false or misleading and which is designed to, or likely to, influence the decision of investors dealing in securities;
 - (j) a market participant entering into transactions on behalf of a client without the knowledge of or instructions from the client or misutilising or diverting the funds or securities of the client held in fiduciary capacity;
 - (k) indulging in circular transactions in respect of any securities to artificially provide a false appearance of trading in such securities or to inflate, depress or cause fluctuations in the price of such securities;
 - (l) fraudulent inducement of any person by a market participant to deal in securities with the objective of enhancing his brokerage or commission or income;
 - (m) predating or otherwise falsifying records, including contract notes, client instructions, balance of securities statement, or client account statements relating to any activity in the securities market;

- (n) any order in securities placed by a person, while directly or indirectly in possession of information that is not publicly available, regarding a substantial impending transaction in that securities, its underlying securities or its derivative;
- (o) knowingly planting false or misleading news which may induce sale or purchase of securities;
- (p) mis-selling of securities or services relating to securities market;

Explanation.— For the purposes of this clause, “mis-selling” means sale of securities or services relating to securities market by any person, directly or indirectly, by:—

- (i) knowingly making a false or misleading statement;
- (ii) knowingly concealing or omitting material facts;
- (iii) knowingly concealing the associated risk; or
- (iv) not taking reasonable care to ensure suitability of the securities or service to the buyer.
- (q) creating artificial demand or price of securities;
- (r) buying and selling securities at the same price in order to artificially increase trading activity;
- (s) dissemination of a rumour or creation of misleading activity which could push the price of securities upward or downward;
- (t) submission of order and cancelling it repeatedly with no intent to execute the order, only to alter the supply or demand to artificially establish demand and price of securities;
- (u) any diversion, misutilisation or siphoning off of the assets or earnings of an entity that would directly or indirectly manipulate the price of its securities;
- (v) manipulation of the books of accounts or financial statements of the entity that would directly or indirectly manipulate the price of its securities; or
- (w) illegal mobilisation of funds by sponsoring or causing to be sponsored or carrying on or causing to be carried on any collective investment scheme by any person;

Explanation.— For the removal of doubts, it is clarified that the acts and omissions listed in this sub-regulation are not exhaustive, and an act or omission is prohibited if it falls within the purview of regulation 7, notwithstanding the fact that it is not included in this sub-regulation or has been described as being committed or omitted only by a certain category of person(s) in this sub-regulation.

CHAPTER IV

MISCELLANEOUS

9. Institutional mechanism for prevention of market abuse.

- (1) Every listed entity shall put in place an adequate and effective system of internal controls and a code of conduct to ensure compliance with these Regulations to prevent market abuse.
- (2) The internal controls shall, inter-alia, provide for the following,—
 - (a) identification and maintenance of confidentiality of material non-public information;
 - (b) placing adequate restrictions on procurement and communication of material non-public information;
 - (c) identification of employees who have access to material non-public information; and
 - (d) periodic review of controls to evaluate their effectiveness.
- (3) Without prejudice to sub-regulations (1) and (2), the Authority may specify such additional standards for internal controls and code of conduct as it may deem fit.

10. Sanction for violations.

Any contravention of these Regulations shall be dealt with by the Authority in accordance with the corresponding provisions of the Act.

11. Suspension or cancellation of registration.

The Authority may, without prejudice to any action under the corresponding provisions of the Act or the regulations made thereunder, by an order for reasons to be recorded in writing and in the interests of investors and securities market, take any of the following actions against a person regulated by the Authority, for contravention of the provisions of these Regulations,—

- (a) issue a warning or censure; or
- (b) suspend or cancel the registration of such person.

12. Power to remove difficulties.

In order to remove any difficulties in the interpretation or application of the provisions of these Regulations, the Authority may issue directions or clarifications through subsidiary instructions.

13. Power to specify norms, procedures, and issue clarifications.

For the purposes of implementing these Regulations and the matters incidental thereto, the Authority may specify norms, procedures, processes or any additional requirements by way of subsidiary instructions, and may issue such clarifications as may be required.

15. Power to relax strict enforcement of the Regulations.

- (1) The Authority may, for reasons to be recorded in writing, in the interest of development of the financial services market in the International Financial Services Centre, relax the strict enforcement of any requirement of these Regulations.
- (2) For seeking relaxation under sub-regulation (1), an application giving details and the grounds on which such relaxation has been sought, shall be filed with the Authority along with such non-refundable fee as may be specified by the Authority.
- (3) The Authority shall process the application filed under sub-regulation (2) within sixty days of the date of receipt of the application, complete in all respects, including responses to clarifications sought and shall record reasons for acceptance or refusal of the relaxation(s) sought by the applicant.

15. Disapplication and savings.

- (1) On and from the commencement of these Regulations, the Securities and Exchange Board of India (Prohibition of Insider Trading) Regulations, 2015, and the Securities and Exchange Board of India (Prohibition of Fraudulent and Unfair Trade Practices relating to Securities Market) Regulations, 2003 shall not apply in the International Financial Services Centre.
- (2) Notwithstanding anything contained in sub-regulation (1), anything done or any action taken or purported to have been taken under the regulations mentioned in sub-regulation (1), prior to the commencement of these Regulations, shall be deemed to have been done or taken under the corresponding provisions of these Regulations.

PRADEEP RAMAKRISHNAN, Executive Director

[ADVT.-III/4/Exty./295/2026-27]



पेंशन निधि विनियामक और विकास प्राधिकरण
PENSION FUND REGULATORY AND DEVELOPMENT AUTHORITY

CIRCULAR

Circular No. PFRDA/2026/49/NPS-SWASTHYA/01

September 18, 2026

To,

- i. Registered intermediaries of PFRDA
- ii. Health Benefit Administrators ('HBAs')
- iii. Association of NPS Intermediaries ('ANPI')
- iv. All other NPS Stakeholders

Madam / Sir,

Subject: Operational Guidelines for NPS Swasthya under the National Pension System (NPS), 2026

1. In exercise of the powers conferred under Section 14 of the Pension Fund Regulatory and Development Authority Act, 2013 read with Regulation 4A of the Pension Fund Regulatory and Development Authority (Exits and Withdrawals under the National Pension System) Regulations, 2015 and all other enabling provisions, the Pension Fund Regulatory and Development Authority (hereinafter referred to as 'Authority') hereby issues the "Operational Guidelines for NPS Swasthya under the National Pension System (NPS), 2026", attached with this Circular.
2. These Guidelines shall apply to all registered intermediaries of PFRDA, HBAs and ANPI. Every PF shall ensure that HBA and insurer engaged by it for implementation of NPS Swasthya complies with the applicable provisions of these Guidelines.
3. All concerned intermediaries shall take necessary steps to ensure compliance with the provisions of the Guidelines attached to this Circular and shall establish appropriate systems, processes and controls for effective implementation of NPS Swasthya.
4. The Authority may issue clarifications, operational instructions or directions, from time to time, for the effective implementation of these Guidelines.
5. This Circular shall come into force with immediate effect.
6. The circular is made available on the PFRDA website (www.pfrda.org.in) in the Circular section under the regulatory framework.

Yours faithfully,

Chief General Manager

ई – 500, टावर – ई, पाचवां तल, वर्ल्ड ट्रेड सेंटर, नौरोजी नगर, नई दिल्ली – 110 029

दूरभाष: 91 – 11 – 40717900, वेबसाइट: www.pfrda.org.in

E – 500, Tower – E, Fifth Floor, World Trade Center, Nauroji Nagar, New Delhi – 110 029

Phone: 91 – 11 – 40717900, Website: www.pfrda.org.in





INDEX

CHAPTER I – PRELIMINARY	4
1. Short title and commencement	4
2. Applicability	4
3. Definitions.....	4
CHAPTER II – NPS SWASTHYA FRAMEWORK	6
4. Eligibility and Account Structure	6
5. Contributions	6
6. Investment.....	6
7. Fees and Charges	7
8. Partial Withdrawals.....	7
9. Transfer from an existing NPS Scheme under All Citizen Model.....	7
10. Change of NPS Swasthya scheme	8
11. Closure of NPS Swasthya Account.....	8
12. Premature Exit.....	8
13. Normal Exit and Exit due to Death	9
14. Non-availability of funds to renew insurance	9
15. Nomination	9
16. Existing NPS Swasthya Subscribers under Regulatory Sandbox.....	9
CHAPTER III – PENSION FUND (PF)	10
17. Governance of NPS Swasthya	10
18. Responsibilities of PF	10
19. Engagement of HBA.....	11
20. Supervision and Oversight of HBA.....	11
CHAPTER IV – HEALTH BENEFIT ADMINISTRATOR (HBA).....	12
21. Empanelment of HBA	12
22. Eligibility Criteria	12
23. Empanelment Process.....	13



24. Engagement Agreement and Service Level Standards.....	14
25. Core Responsibilities of HBA.....	15
26. Monitoring, Review and Corrective Action	16
27. Suspension, Termination and Orderly Transition	16
28. Compliance with Directions.....	17
CHAPTER V – INSURANCE POLICY.....	17
29. Insurance Policy	17
30. Standard Insurance Policy	18
31. Insurance Premium	21
CHAPTER VI – CENTRAL RECORDKEEPING AGENCY (CRA), TRUSTEE BANK AND POINT OF PRESENCE (PoP)	22
32. Responsibilities of CRA	22
33. Responsibilities of Trustee Bank.....	23
34. Responsibilities of Point of Presence.....	23
CHAPTER VII – TECHNOLOGY, SUBSCRIBER DISCLOSURE AND GRIEVANCE REDRESSAL	23
35. Technology and Operational Framework	23
36. Disclosures.....	24
37. Grievance Redressal	25
CHAPTER VIII – REPORTING, COMPLIANCE AND REGULATORY POWERS.....	25
38. Regulatory Reporting.....	25
39. Compliance	26
40. Power to Call for Information	26
41. Power to Issue Directions and Interpretation	27



“NPS Swasthya seeks to enable subscribers to build a dedicated corpus for meeting retirement expenses while facilitating access to health insurance and healthcare-related services through the ecosystem established under NPS architecture. The Scheme provides greater flexibility for healthcare-related withdrawals and specified exit options to enable subscribers to meet eligible healthcare expenses in an efficient and timely manner.”

CHAPTER I – PRELIMINARY

1. Short title and commencement

1.1. These Guidelines may be called the “Operational Guidelines for NPS Swasthya under the National Pension System (NPS), 2026”.

1.2. These Guidelines are issued under Regulation 4A of the Pension Fund Regulatory and Development Authority (Exits and Withdrawals under the National Pension System) Regulations, 2015, and shall come into force from the date specified by the Authority through a circular.

2. Applicability

2.1. These Guidelines shall apply to registered intermediaries of PFRDA participating in NPS Swasthya and shall also apply to the Association of NPS Intermediaries (ANPI) and Health Benefit Administrators (HBAs).

2.2. An insurer and its Third Party Administrator (TPA) shall participate in NPS Swasthya for the purpose of super top-up insurance policy in accordance with the applicable insurance law. Their registration, insurance conduct, product terms, premium, underwriting, policy issuance, claims and insurance related grievances shall remain governed by Insurance Regulatory and Development Authority of India (IRDAI).

2.3. Nothing contained in these Guidelines shall be construed as authorising any entity to undertake insurance solicitation, distribution, underwriting, policy issuance, claim adjudication, TPA activity or any other insurance activity without the registration, permission or appointment required under applicable insurance law.

3. Definitions

Unless the context otherwise requires:

3.1. “Act” means the Pension Fund Regulatory and Development Authority Act, 2013.



3.2. “Eligible Healthcare Expense” means a healthcare expense permitted to be met from the NPS Swasthya corpus under these Guidelines, irrespective of whether the expense is admissible under the Insurance Policy.

3.3. “Health Benefit Administrator” or “HBA” means an entity empanelled by ANPI and engaged by a PF to perform pension-side technology, account-administration, authorization-coordination, recordkeeping, subscriber-interface functions, healthcare technology platform services under NPS Swasthya in accordance with these Guidelines. An HBA is not, by reason of such empanelment, an insurer, TPA or insurance intermediary.

3.4. “Insurer” means an entity registered with the IRDAI and engaged by a PF for NPS Swasthya.

3.5. “Insurance Policy” means a super top-up health insurance policy provided by an insurer engaged by PF under master policy arrangement in respect of NPS Swasthya.

3.6. “NPS Swasthya” means the pension scheme for a specific purpose introduced under Regulation 4A of the Pension Fund Regulatory and Development Authority (Exits and Withdrawals under the National Pension System) Regulations, 2015, to facilitate retirement savings together with such healthcare benefits and insurance policy as may be specified under these Guidelines.

3.7. “NPS Swasthya Corpus” means the net asset value of units outstanding in the NPS Swasthya account of a subscriber.

3.8. “Super Top-up insurance” means a supplementary insurance plan that covers total yearly medical expenses once a deductible threshold is crossed. It considers the total medical costs incurred in a policy year, not just individual claims.

3.9. “Third Party Administrator” or “TPA” means an entity appointed by the insurer in accordance with applicable insurance law.

3.10. Words and expressions used but not defined in these Guidelines shall have the meanings assigned to them under the Act, the regulations framed thereunder and the circulars, guidelines or directions issued by the Authority. Insurance expressions shall, where relevant, have the meanings assigned under applicable insurance law and the Insurance Policy.

CHAPTER II – NPS SWASTHYA FRAMEWORK

4. Eligibility and Account Structure

4.1. Any individual eligible to join NPS may enroll under NPS Swasthya, subject to these Guidelines.

4.2. NPS Swasthya shall comprise of,-

- (i). an account with an NPS Swasthya investment scheme; and
- (ii). a separate super top-up health insurance policy.

4.3. The Insurance Policy shall be mandatory for enrolment under NPS Swasthya. The NPS Swasthya Account and the Insurance Policy shall remain legally and operationally distinct.

4.4. The standard super top-up health insurance under NPS Swasthya, to be provided by an insurer engaged by the PF under master policy arrangement, shall be subject to applicable insurance laws.

5. Contributions

5.1. The minimum initial contribution shall be at least,-

- (i). the applicable first-year Insurance Policy premium, inclusive of applicable taxes;
- (ii). annual maintenance charges of ₹200, plus applicable taxes, payable to HBA through PFs for undertaking servicing of NPS Swasthya scheme; and
- (iii). ₹1,000 towards investment in the NPS Swasthya account.

5.2. The minimum subsequent contribution to NPS Swasthya shall be ₹10.

5.3. The premium shall be remitted to the insurer in accordance with the prescribed fund-flow process given in the Standard Operating Procedure (SoP).

6. Investment

6.1. Contributions received under NPS Swasthya shall be invested in accordance with the investment pattern prescribed for the Central Government Scheme under the applicable PFRDA investment guidelines.

6.2. Each PF shall maintain a separate scheme account for NPS Swasthya.

6.3. The Authority may modify the applicable investment pattern from time to time.



7. Fees and Charges

7.1. The charges applicable to NPS under the All Citizen Model, as specified by the Authority, shall apply to NPS Swasthya. In addition, the PF may levy,-

(i). a charge upto 0.08% per annum of the AUM of the NPS Swasthya corpus, plus applicable taxes for managing the NPS Swasthya; and

(ii). annual maintenance charges of ₹200, plus applicable taxes, payable to HBA through PFs for undertaking servicing of NPS Swasthya scheme.

7.2. All charges shall be disclosed to the subscriber before enrolment and upon any change therein.

7.3. No charge other than a charge permitted or approved by the Authority shall be recovered from the subscriber.

8. Partial Withdrawals

8.1. A subscriber may make a partial withdrawal towards Eligible Healthcare Expenses, including eligible out-patient and in-patient expenses, in accordance with these Guidelines.

8.2. The amount of partial withdrawals shall not exceed twenty-five per cent of the contributions made by the subscriber to the NPS Swasthya account.

8.3. There shall be no restriction on the number of partial withdrawals. No minimum waiting period shall apply to the first or any subsequent partial withdrawal.

8.4. The partial withdrawal amount shall not be paid to the subscriber. The amount shall be settled with the concerned hospital, healthcare provider or other eligible entity towards the Eligible Healthcare Expenses, in accordance with the prescribed fund-flow process given in the SoP.

9. Transfer from an existing NPS Scheme under All Citizen Model

9.1. A subscriber may transfer funds from an existing NPS scheme under the All Citizen Model to the NPS Swasthya account, subject to the amount being limited to meet the applicable deductible under the Insurance Policy.



10. Change of NPS Swasthya scheme

10.1. A subscriber may change from one NPS Swasthya scheme to another at the time of renewal of the insurance policy, in the manner specified by the Authority. Such change may involve a change of PF and the associated insurance policy.

10.2. The PF shall ensure that the outgoing and incoming insurers comply with applicable requirements relating to migration, portability, waiting periods, moratorium and continuity credits, in accordance with applicable insurance laws and directions issued by IRDAI.

10.3. The PF shall ensure that the outgoing insurer remains responsible for claims arising during its policy period, in accordance with the insurance policy and applicable law. A switch shall not affect any admitted, pending or reopened insurance claim or grievance.

11. Closure of NPS Swasthya Account

11.1. An NPS Swasthya account shall be closed upon: (i). normal exit; (ii). premature exit; (iii). non-availability of funds to renew insurance; or (iv) death of the subscriber.

11.2. Closure of the NPS Swasthya account shall not affect any other NPS account maintained by the subscriber.

12. Premature Exit

12.1. A subscriber may opt for premature exit from the NPS Swasthya account where eligible inpatient healthcare expenditure in a single instance exceeds the amount permissible through partial withdrawal.

12.2. On premature exit, the accumulated NPS Swasthya corpus shall first be utilised towards the eligible in-patient healthcare expenditure. In case of any remaining balance, NPS Swasthya scheme shall be closed and merged to an NPS scheme under the All Citizen Model. Where the subscriber does not have an existing NPS scheme under the All Citizen Model, the NPS Swasthya scheme shall be changed into an NPS scheme under the All Citizen Model.

12.3. Upon such change, the NPS Swasthya account shall stand closed. Any Insurance Policy already in force shall continue for its remaining policy period, in accordance with its terms and applicable insurance law.



13. Normal Exit and Exit due to Death

13.1. The exit provisions applicable to non-Government subscribers under the Pension Fund Regulatory and Development Authority (Exits and Withdrawals under the National Pension System) Regulations, 2015, shall apply to NPS Swasthya.

14. Non-availability of funds to renew insurance

14.1. Where the available balance may be insufficient for renewal premium, the PF shall, where practicable, alert the subscriber at least 90, 60 and 30 days before renewal. The applicable grace period and consequences of non-payment shall be disclosed clearly. If premium remains unpaid after the applicable grace period and cover lapses, the NPS Swasthya shall be treated as closed.

14.2. In such cases, NPS Swasthya scheme shall be closed and merged to an NPS scheme under the All Citizen Model. Where the subscriber does not have an existing NPS scheme under the All Citizen Model, the NPS Swasthya scheme shall be changed into an NPS scheme under the All Citizen Model.

15. Nomination

15.1. The nomination provisions applicable to non-Government subscribers under the Pension Fund Regulatory and Development Authority (Exits and Withdrawals under the National Pension System) Regulations, 2015, shall apply to NPS Swasthya.

16. Existing NPS Swasthya Subscribers under Regulatory Sandbox

16.1. The NPS Swasthya schemes offered under the Regulatory Sandbox shall be discontinued upon implementation of these Guidelines.

16.2. Existing subscribers under the NPS Swasthya scheme offered under the Regulatory Sandbox shall be provided an option to migrate to an NPS Swasthya scheme offered under these Guidelines, in the manner specified by the Authority.

16.3. Such subscribers may also opt to merge their NPS Swasthya Scheme to an NPS scheme under the All Citizen Model, in accordance with the prescribed process. Where the subscriber does not have an existing NPS scheme under the All Citizen Model, the NPS Swasthya scheme shall be changed into an NPS scheme under the All Citizen Model.

16.4. The PF, CRA and other intermediaries concerned shall facilitate such migration or transfer and ensure continuity of the subscriber's records, benefits and applicable insurance coverage, in accordance with the prescribed process.

CHAPTER III – PENSION FUND (PF)

17. Governance of NPS Swasthya

17.1. NPS Swasthya shall be offered and managed by PFs registered with the Authority, in accordance with the Act, regulations, these Guidelines and the conditions of approval.

17.2. Every PF offering NPS Swasthya shall maintain an adequate governance, operational, technology, risk and control framework covering NPS Swasthya administration, HBA engagement, the insurance policy, data governance, conflicts of interest, grievance handling, business continuity and orderly migration or exit.

17.3. Engagement of an HBA, insurer or any service provider shall not absolve the PF of its responsibilities under the Act, the regulations, these Guidelines or the directions issued by the Authority.

17.4. The PF shall remain solely responsible for ensuring compliance with all regulatory requirements relating to NPS Swasthya, irrespective of whether any activity is performed directly or through an HBA.

18. Responsibilities of PF

18.1. Design, implement and administer NPS Swasthya in accordance with these Guidelines and the approval granted by the Authority.

18.2. Select and engage an empanelled HBA through a transparent process, execute the agreement and monitor the performance of the HBA.

18.3. Select an eligible participating insurer through a transparent process and maintain the insurance policy required for NPS Swasthya. The insurer shall not be a promoter-group, holding, subsidiary, associate or common-control entity of the PF.

18.4. Act as the master policyholder only where permitted under applicable insurance law and the Insurance Policy.

18.5. Monitor the performance of the HBA(s) and insurer engaged under NPS Swasthya and take appropriate corrective action, wherever necessary.

18.6. Establish systems for subscriber servicing, grievance redressal, incident management, data quality, business continuity and regulatory reporting.

18.7. Maintain adequate records relating to the administration of NPS Swasthya and furnish such information to the Authority, in such form and manner, as may be specified.



18.8. Not receive any insurance commission, premium share, claim-linked payment or other insurance consideration that may create a conflict with the interests of subscribers.

18.9. Ensure compliance with the Act, regulations, these Guidelines and directions issued by the Authority from time to time.

19. Engagement of HBA

19.1. A PF may engage one or more HBAs from the panel maintained by ANPI.

19.2. The engagement of an HBA shall be governed by a written agreement specifying the scope of services, service levels, fees, confidentiality, data roles, information security, business continuity, reporting, audit rights, conflicts of interest, liability, dispute resolution, termination and transition arrangements.

19.3. The HBA fee shall be as given in clause 7.1.

19.4. Where more than one HBA is engaged, the PF shall clearly allocate responsibilities and ensure seamless subscriber servicing and portability of records.

20. Supervision and Oversight of HBA

20.1. The PF shall establish an effective oversight mechanism to monitor the performance, compliance and service standards of each HBA engaged by it.

20.2. The PF shall ensure that each HBA provides timely access to information, records and documents required for compliance with the Act, regulations, these Guidelines and directions issued by the Authority.

20.3. The PF shall conduct periodic reviews of the service level agreements and controls and undertake due diligence of each HBA at least annually. Any deficiencies identified shall be addressed through a time-bound corrective action plan.

20.4. Any material breach, harm to subscribers, data incident or loss of eligibility of an HBA shall be reported promptly to ANPI and the Authority.

20.5. The Authority may call for such information, records or documents relating to NPS Swasthya from the PF as it may deem necessary. The PF shall obtain and furnish such information, records or documents from the HBA or insurer, as may be required by the Authority.

20.6. Notwithstanding the above, the Authority shall have the power to call for such information, records or documents relating to NPS Swasthya directly from the HBA(s), as it may deem necessary.

CHAPTER IV – HEALTH BENEFIT ADMINISTRATOR (HBA)

21. Empanelment of HBA

21.1. ANPI shall empanel HBAs in close conjunction with the Authority through a transparent, and objective process.

21.2. The empanelment criteria, evaluation methodology, standard agreements and material decisions relating to the empanelment of HBAs shall be formulated in consultation with the Authority.

21.3. ANPI shall maintain and publish the current panel of HBAs and shall place empanelment, review, suspension and termination decisions before the Authority.

21.4. The Authority may seek records, participate in or observe the evaluation process, require reconsideration or corrective action, and issue directions in the interest of subscribers and the orderly development of NPS Swasthya.

21.5. Only an HBA on the current ANPI panel may be engaged by PF for NPS Swasthya.

21.6. Empanelment of an HBA by ANPI shall not dispense with the requirement for a separate engagement agreement between the HBA and the PF.

22. Eligibility Criteria

An applicant desirous to act as an HBA shall fulfill the following eligibility criteria as on the day of making an application.

22.1. The applicant or its promoter shall be,—

- (i). a body corporate incorporated under the Companies Act, 2013; and
- (ii). in continuous operation for at least two years;

22.2. The applicant or its promoter shall have,—

- (i). a net worth of at least rupees five crore, as on the last day of the preceding financial year.

Explanation.- Net worth means as defined under section 2(57) of the Companies Act, 2013;

- (ii). an average annual turnover of at least rupees five crore during the three preceding financial years;
- (iii). at least two years of relevant experience in healthcare, health-benefit administration or healthcare transaction processing; and
- (iv). a valid ISO/IEC 27001 certification.

22.3. The applicant or its promoter shall demonstrate,—

- (i). provider connectivity supported by at least 5,000 completed IPD and/or OPD transactions;
- (ii). the capacity to process at least 5,000 transactions per month; and
- (iii). a two way switch/ integration between the HBA and the TPA in order to have a seamless and smooth flow of data and exchange of information between the two systems at all times.

22.4. The applicant and its key personnel shall be a 'fit and proper person' as specified in the empanelment framework.

22.5. While filing the application for empanelment, the applicant shall disclose all relevant information including any action or legal proceedings initiated against it, its key personnel in the past including the pending proceedings, for any material breach or non-compliance by them of any law, rules, regulations, and directions of the Authority or of any other regulatory body or the Government.

22.6. The applicant shall inform the ANPI and the Authority of any changes in the information furnished at the time of making an application, within seven days of such change.

22.7. The HBA shall maintain secure, scalable and interoperable systems, tested APIs, annual vulnerability assessment and penetration testing by a CERT-In empanelled auditor, appropriate Indiabased processing or storage where prescribed by law, and tested business continuity and disaster recovery arrangements.

22.8. HBA shall, at all times, comply with the eligibility criteria specified in these guidelines and other requirements laid down under the empanelment framework.

23. Empanelment Process

23.1. ANPI shall invite applications in the form and manner specified under the empanelment framework.

23.2. ANPI shall verify documentary compliance with the minimum eligibility criteria and seek clarifications, wherever required.

23.3. Operational, provider-network, technology, cybersecurity, financial and fit-and-proper due diligence shall be completed before empanelment.

23.4. ANPI shall record the evaluation and the decision or recommendation in accordance with the empanelment framework.

23.5. Before commencement of operations, the HBA shall execute the agreement and service level agreement and complete end-to-end user acceptance, security, load and business-continuity testing.

24. Engagement Agreement and Service Level Standards

24.1. The HBA engagement agreement shall contain written provisions relating to scope of services, measurable service levels, fees, confidentiality, information security, data roles, business continuity, incident reporting, records, audit rights, conflicts of interest, intellectual property, indemnity, liability, dispute resolution, termination and transition.

24.2. The minimum service standards shall be as specified in the Table below or otherwise prescribed by the Authority. A PF may prescribe stricter standards but shall not dilute the minimum standards.

SLA	Minimum standard	Measurement
Platform uptime	At least 99.5% in each calendar month	Monthly
API response	95th percentile within 1 second	Monthly
Planned IPD corpus authorization	Within 1 working hour of receipt of complete documentation	Per transaction
HBA-to-insurer/TPA referral	Within 5 minutes of a complete request meeting the trigger	Per transaction
Status synchronization	Update within 5 minutes of receipt of status	Per transaction
Document-once	No repeat request for a document already available, unless necessity for such request is recorded	Per transaction
Settlement intimation	Within 7 working days of receipt of final billing documents, for the NPS Swasthya corpus	Per transaction

SLA	Minimum standard	Measurement
HBA-service grievances	At least 90% resolved within 7 working days and 100% resolved within 15 working days	Monthly
Material incident	Initial report within 24 hours and detailed report within 7 days, subject to any stricter legal requirement	Event based

25. Core Responsibilities of HBA

An HBA engaged under NPS Swasthya shall,—

25.1. facilitate healthcare benefits and healthcare-related services in accordance with these Guidelines and the agreement with the PF;

25.2. facilitate verification and processing of healthcare-related requests and supporting documents submitted by subscribers, hospitals or healthcare service providers, as applicable;

25.3. verify withdrawal eligibility, the applicable withdrawal limit and available corpus, eligibility of healthcare expenses and the amount payable through the NPS Swasthya corpus in accordance with these guidelines;

25.4. provide the information required for balance verification, lien marking, redemption and settlement of eligible healthcare expenses and facilitate the settlement thereof through the prescribed process;

25.5. communicate the amount payable through NPS Swasthya to the concerned hospital or healthcare service provider, as applicable;

25.6. maintain adequate technological, operational and information-security arrangements, including appropriate access controls, for discharge of its responsibilities;

25.7. facilitate the subscriber-facing digital interface for the healthcare journey under NPS Swasthya and provide accurate information relating to eligibility for withdrawal, available balance, authorisation and transaction status;

25.8. maintain an accurate transaction trail and facilitate reconciliation of each healthcare encounter under the NPS Swasthya;

25.9. maintain appropriate controls to prevent and detect duplicate, fraudulent or anomalous healthcare requests and transactions;



25.10. ensure grievance redressal at the first instance in respect of services provided by the HBA and facilitate resolution of other healthcare-related grievances by routing them to the responsible entity, as applicable;

25.11. protect subscriber and health data and ensure confidentiality, security and access to such data only for authorised NPS Swasthya purposes;

25.12. maintain such records and transaction information as may be required for discharge of its responsibilities under these Guidelines and provide access to such records to the PF, ANPI, the Authority or an authorised entity by the Authority, as applicable;

25.13. submit such operational, financial, audit, security and incident reports as may be specified by ANPI, the PF or the Authority; and

25.14. act honestly, fairly, professionally and with due skill, care and diligence and shall not solicit or advise on insurance, guarantee payment of an insurance claim, steer subscribers to healthcare service providers for any undisclosed benefit, levy any unauthorised charge or use subscriber or health data for unrelated marketing or profiling.

25.15. Accountability for functions assigned to the HBA shall remain with the HBA and shall not be delegated in a manner that dilutes its responsibility under these Guidelines.

26. Monitoring, Review and Corrective Action

26.1. Empanelment of an HBA shall be subject to periodic review of its eligibility, fit-and-proper status, financial soundness, ISO/IEC 27001 certification, service levels, data quality, grievances, security controls and HBA performance.

26.2. For non-compliance, ANPI may, after consultation with the Authority, issue a warning, require a time-bound remediation plan, suspend the HBA or terminate empanelment.

26.3. Except where immediate interim action is necessary to protect subscribers, funds, data or system integrity, the HBA shall be given a reasonable opportunity to respond before an adverse empanelment decision is taken.

26.4. The Authority may inspect or require an independent audit of the HBA's functions under NPS Swasthya.

27. Suspension, Termination and Orderly Transition

27.1. In case of suspension or termination, an HBA shall ensure continuity of services to existing subscribers and shall not adversely affect pending NPS Swasthya transactions.



27.2. The HBA shall protect subscriber data and securely transfer pending transactions, records and operational responsibilities to an alternate empanelled HBA engaged by the PF, within the period specified by ANPI in consultation with the Authority.

27.3. The transition and migration shall be completed securely and in accordance with applicable law, the engagement agreement and directions issued by the Authority.

28. Compliance with Directions

28.1. The HBA shall comply with the reporting requirements, operational standards and directions issued by the Authority in relation to its functions under NPS Swasthya.

28.2. The HBA shall ensure that its systems, personnel, processes and arrangements remain compliant with the applicable provisions of the Act, regulations, these Guidelines and the directions issued by the Authority from time to time.

CHAPTER V – INSURANCE POLICY

29. Insurance Policy

29.1. Every PF offering NPS Swasthya shall arrange a standard super top-up health insurance policy through an insurer registered with IRDAI, as specified under Clause of 30 & 31 of these guidelines.

29.2. The Insurance Policy shall be issued under a master policy or other group arrangement permitted under applicable insurance law. PF shall ensure that each subscriber or covered member is provided with the insurance policy, certificate of insurance, customer information sheet and other insurance related documents.

29.3. Before availing the services of an insurer, the PF shall evaluate the insurer based on, inter-alia, the scope of super top-up health insurance policy, servicing standards, claims administration, premium remittance, data sharing, grievance handling, reporting obligations and other operational matters. The PF shall also enter into an appropriate arrangement with the insurer to monitor the implementation and servicing of the insurance policy.

29.4. Insurance policy under NPS Swasthya shall commence not later than T+1 working days from the date of successful enrolment of the subscriber under NPS Swasthya and receipt of the applicable minimum initial contribution, where T denotes the date of successful enrolment.



29.5. The PF shall ensure that the insurance policy remains valid for as long as insurance benefits are offered under NPS Swasthya and shall provide for orderly transition in the event of a change of insurer.

29.6. Renewal and continuity, including waiting-period, migration, portability and moratorium credits, shall be governed by applicable insurance law and IRDAI directions. A PF initiated change of insurer shall be so undertaken in order to avoid break in cover.

29.7. Before enrolment, all material terms of the insurance policy, including sum insured, Annual Aggregate Deductible, exclusions, waiting periods, premium, renewal conditions, underwriting requirements, claim process and grievance redressal mechanism, shall be disclosed to the subscriber.

29.8. A PF shall not onboard an insurer-specific version of the Insurance Policy that differs from the standard Insurance Policy.

30. Standard Insurance Policy

30.1. Eligibility and cover

(i). Master policyholder: the PF, where permitted under applicable insurance law.

(ii). Coverage unit: subscriber, spouse and up to two dependent children as one family floater; parents are excluded.

(iii). Subscriber entry age: 18 to 70 years. Entry-age premium cohorts: 18 to 40 years; above 40 to 60 years; above 60 to 70 years. Renewal may continue up to and including age of 85 years, subject to premium, policy terms and applicable law.

(iv). The Annual Aggregate Deductible shall apply to cumulative Insurance - Admissible Expenses of all covered family members during the Policy Year and shall not apply separately to each claim.

Annual Aggregate Deductible	₹ 10,000	₹ 50,000	₹1 lakh	₹3 lakh
Family Floater Sum Insured	₹1 lakh	₹5 lakh	₹10 lakh	₹30 lakh

(v). Room entitlement: single private room for normal hospitalisation; ICU charges at actuals, subject to sum insured and the final policy wording.

(vi). Pre-hospitalisation: 30 days. Post-hospitalisation: 60 days. Road ambulance: up to ₹2,500 per emergency hospitalisation, unless a higher uniform limit is provided in the final policy.



(vii). The policy shall cover medically necessary day-care procedures, inpatient hospitalisation, domiciliary hospitalisation, AYUSH treatment, prescribed modern treatments and organ-donor medical expenses, subject to the final policy wording.

(viii). No co-payment or disease-specific sub-limit shall apply. Consumables and non-payables shall be as per the standard top-up insurance policy;

(ix) an Eligible Healthcare Expense not paid by insurance may be considered from the NPS Swasthya corpus.

30.2. Waiting periods, underwriting and continuity

(i). Initial waiting period: 30 days, except for accident as provided in the final policy wording.

(ii). Pre-existing disease waiting period: 12 months.

(iii). Specified disease or procedure waiting period: 12 months, subject to the final Insurance Policy and applicable insurance law.

(iv). Controlled Type 2 diabetes, hypertension, hyperlipidaemia and asthma that do not trigger enhanced underwriting under the prescribed Good Health Declaration shall be covered after the initial waiting period of 12 months.

(v). Fresh underwriting at renewal shall not be imposed except where sum insured is enhanced.

(vi). Waiting-period, migration, portability, moratorium and other continuity credits shall be carried forward on change of insurer and/or PF in accordance with insurance law and IRDAI directions.

(vii). An insurance decision based on material non-disclosure shall not by itself bar payment of a genuine Eligible Healthcare Expense from the NPS Swasthya corpus. A fabricated or fraudulent healthcare request shall not be paid from the corpus.

30.3. Good Health Declaration

(i). Insurance enrolment shall ordinarily be based on the prescribed Good Health Declaration.

(ii). Subscriber shall answer for himself/herself and on behalf of his/her spouse and his/her dependent children, whether he/she or any of family member/s is suffering from, has been diagnosed with, has been advised or has taken treatment for, or has undergone or been

advised surgery for, any of the following conditions, subject to the final question set permitted under the IRDAI-approved or filed policy:

S. No.	Condition
1	Heart attack.
2	Stroke, paralysis in any form, or any other cerebrovascular disease.
3	Thyroid or parathyroid disease; chronic or acute kidney disease.
4	Acute or chronic liver failure or disease, cirrhosis of liver, alcoholic liver disease, or pancreatic disease.
5	Lung disease.
6	Blood disorders or gastrointestinal disease such as peptic ulcer.
7	Disorder of the bones, spine or muscle.
8	Cancer or cancerous growth, benign or malignant tumour.
9	Autoimmune disease or disease related to the central nervous system or brain.
10	HIV/AIDS or AIDS-related complications.
11	History of sudden loss of weight in the last one year.
12	Head injury.
13	Major burns.
14	Type 1 diabetes and/or treatment with insulin.
15	Asthma with more than two hospitalisations in the last one year, acute severe bronchial asthma or status asthmaticus.

(iii). Where a declaration triggers enhanced underwriting, the insurer shall apply the applicable premium loading based on the declaration, without requiring formal medical reports. Where the proposal is declined, the subscriber shall be communicated the specific reason for such decline in accordance with applicable law. Decline of coverage in respect of one family member shall not, by itself, disqualify other eligible family members, subject to the terms of the Insurance Policy.

30.4. Minimum claims and service controls

Service	Minimum requirement
Cashless pre-authorisation	Within one hour of a complete request, or any stricter applicable IRDAI timeline.

Final discharge authorisation	Within three hours of a complete hospital request, or any stricter applicable IRDAI timeline.
HBA referral/status synchronisation	Referral within 5 minutes and status update within 5 minutes of receipt.
Reimbursement target	Within 15 calendar days of the last necessary document, subject to the applicable IRDAI timeline.
Documents	Required hospital or insurance documents to be collected through the insurer/TPA process; subscriber document-once principle to apply.
Adverse decision	Specific policy clause, standard reason code, amount calculation and appropriate grievance route.

31. Insurance Premium

31.1. The insurer shall determine premium in accordance with the IRDAI framework. For Scheme comparability, premium shall be quoted for the entry age cohorts 18 to 40 years, above 40 to 60 years, and above 60 to 70 years, based on completed age at initial entry.

31.2. The insurer's quote for premium shall include insurer and TPA costs; applicable taxes shall be shown separately. No mid-term premium revision shall apply to an issued policy except as permitted by applicable insurance law.

31.3. Renewal premium changes shall be governed by the applicable insurance law and shall not be imposed merely because an individual subscriber made a claim.

31.4. The first-year premium shall be paid upfront as part of the minimum initial funding requirement and remitted to the insurer through the prescribed fund-flow process as given in the SoP.

31.5. Renewal premium may be funded from the NPS Swasthya corpus and as per the subscriber mandate in accordance with these guidelines. The amount shall be remitted to the insurer through the prescribed fund-flow process as given in the SoP.

31.6. The PF shall maintain controls and advance alerts so that avoidable operational delay in premium remittance does not interrupt cover.



**CHAPTER VI – CENTRAL RECORDKEEPING AGENCY (CRA), TRUSTEE BANK AND
POINT OF PRESENCE (PoP)**

32. Responsibilities of CRA

32.1. Provide the technology and recordkeeping support required for implementation and operation of NPS Swasthya in accordance with these guidelines.

32.2. Facilitate onboarding and registration of subscribers and open and maintain the NPS Swasthya account under the PRAN.

32.3. Maintain records of the PF, HBA, scheme mapping, contributions, units, NAV, own-contribution, healthcare withdrawals, premium mandates, nominations, exits and other details related to NPS Swasthya.

32.4. Facilitate transmission of relevant subscriber, account, insurance and transaction-related information among the PF, insurer, HBA and other entities, as may be required for operation of NPS Swasthya.

32.5. Facilitate processing of healthcare withdrawal and exit requests, including transmission of instructions relating to lien marking, redemption and settlement, in accordance with the approved process.

32.6. Record healthcare withdrawal, redemption, premium instruction and settlement transactions in the subscriber's statement and other applicable records.

32.7. Provide subscriber access to account information, transaction confirmations and statements as prescribed.

32.8. Route grievances related to NPS Swasthya (excluding insurance policy) through the applicable PFRDA grievance mechanism and provide information required by the PF for resolution.

32.9. Reconcile the transactions related to NPS Swasthya, with the PF, Trustee Bank and HBA in accordance with these guidelines and report material exceptions, incidents or unauthorised instructions promptly.

32.10. Provide such information, records and reports relating to NPS Swasthya as may be required by the Authority; and

32.11. Undertake such other functions as may be specified by the Authority from time to time.



33. Responsibilities of Trustee Bank

33.1. Receive and account for contributions relating to NPS Swasthya and transfer funds for investment in accordance with valid instructions under the NPS architecture.

33.2. Execute only duly validated and authorised fund instructions for investment, premium remittance, healthcare settlement, corpus transfer and exit.

33.3. Remit amounts for settlement of claims to the designated hospital, healthcare provider, subscriber or other approved payee in accordance with the CRA instruction.

33.4. Remit insurance premium in accordance with these guidelines.

33.5. Maintain appropriate records of receipts, transfers, redemptions and payments relating to NPS Swasthya;

33.6. Undertake reconciliation of transactions relating to NPS Swasthya with the CRA, PF and other concerned entities, as may be required; and

33.7. Furnish such information, records and reports as may be required by the Authority.

34. Responsibilities of Point of Presence

34.1. The Point of Presence shall perform such functions in relation to NPS Swasthya as may be specified by the Authority from time to time.

34.2. The PoP shall comply with the applicable provisions of the Act, regulations, these Guidelines and directions issued by the Authority in relation to activities undertaken under NPS Swasthya.

CHAPTER VII – TECHNOLOGY, SUBSCRIBER DISCLOSURE AND GRIEVANCE

REDRESSAL

35. Technology and Operational Framework

35.1. All participating entities shall implement the architecture and process-flows prescribed for NPS Swasthya and complete end-to-end user acceptance, security, load, disaster-recovery and negativescenario testing before go-live for each operating combination.

35.2. The HBA shall provide the single digital front for healthcare status and coordination.

35.3. Data sharing shall be necessary, proportionate, purpose-specific and based on recorded consent or another lawful basis. Health data shall not be used for unrelated marketing, profiling



or provider steering. Applicable cybersecurity, data-protection, localisation, encryption, access-control and retention requirements shall be followed.

35.4. The PF shall ensure seamless integration of the systems of the PF, CRAs, Trustee Bank, HBAs, insurers and other participants for onboarding, account servicing, insurance administration, healthcare benefit administration, withdrawals, redemption, settlement and grievance redressal.

35.5. All participating entities shall establish appropriate controls to ensure accuracy, security, confidentiality, integrity and timely transmission of information and settlement of funds.

35.6. A material cybersecurity, privacy, availability or payment incident shall be contained, notified, investigated and remediated in accordance with the applicable PFRDA, CERT-In and data-protection requirements, having regard to the regulatory responsibility of the affected entity.

35.7. The PF shall ensure appropriate reconciliation of information and fund flows among the CRA, Trustee Bank, PF, HBA, insurer and other concerned entities.

35.8. The PF shall ensure that appropriate audit trails are maintained for all material information and fund-flow transactions undertaken under NPS Swasthya.

36. Disclosures

36.1. The PF shall ensure that every subscriber receives complete, accurate, clear and timely information about NPS Swasthya before enrolment and throughout the tenure of the account.

36.2. Before activation and at each renewal, the subscriber shall receive copy of PRAN card, details of HBA, details of Insurer, details of TPA and insurance policy related documents.

36.3. Disclosures shall clearly cover, including but not limited to, initial contribution, charges related to NPS Swasthya, super top-up health insurance policy benefits, insurer, TPA, premium, deductible, exclusions, waiting period, insurance variants and deductible, family coverage, claims process and grievance redressal mechanism.

36.4. Insurance premium and taxes shall be shown separately from NPS Swasthya account charges.

36.5. The subscriber shall be informed of a material change as early as practicable and before it takes effect where advance notice is possible. Any insurance change shall also be

communicated in the manner required under applicable insurance law and the Insurance Policy.

36.6. Every adverse decision under NPS Swasthya shall be displayed and conveyed to the subscriber along with applicable reason in plain language and state the appropriate escalation route.

37. Grievance Redressal

37.1. The subscriber shall be able to lodge a grievance through the Pension Sahayak platform which will enable subscribers to lodge grievances against any stakeholder namely PF, CRAs, POPs, HBAs, Insurers, etc for quick and effective resolution of its grievance.

37.2. The PF shall establish an effective mechanism for redressal of grievances relating to NPS Swasthya. Where a grievance pertains to services rendered by an HBA and insurer engaged under NPS Swasthya, the PF shall coordinate with the concerned entity to facilitate timely resolution.

37.3. The PF shall monitor the resolution of grievances and ensure compliance with the timelines specified by the Authority.

37.4. The insurer shall be responsible for grievance redressal arising out of claim settlement process and any incidental matters to super top-up health insurance policy, in terms of applicable IRDAI Regulations.

37.5. The HBA shall provide a single grievance reference for grievances relating to the healthcare journey and shall coordinate with the concerned entity, as applicable, and remain responsible for closure and escalation in relation to the HBA services.

CHAPTER VIII – REPORTING, COMPLIANCE AND REGULATORY POWERS

38. Regulatory Reporting

38.1. The PF shall furnish periodic reports to the Authority on enrolment, contributions, withdrawals, exits, HBA performance, integrated service levels and such information as is necessary to assess operation of NPS Swasthya.

38.2. The PF shall furnish such returns, reports and information relating to NPS Swasthya as may be required by the Authority from time to time.

38.3. Every intermediary engaged under NPS Swasthya shall furnish such reports and information as may be required by the Authority in such form and manner and within such time as may be specified.

38.4. ANPI may maintain HBA-wise and insurer-wise operational dashboards using common definitions and without personal data. Comparable service metrics may be published in the manner specified by the Authority.

38.5. HBA eligibility failure, persistent service slippage, data misreporting, subscriber harm, cybersecurity failure or failure to implement corrective action shall be reported promptly to the Authority.

39. Compliance

39.1. Every PF shall ensure compliance with these Guidelines and the conditions imposed by the Authority for NPS Swasthya.

39.2. The PF shall maintain adequate internal controls, risk management, audit, business continuity and monitoring arrangements for effective implementation of NPS Swasthya.

39.3. Every PFRDA-regulated intermediary participating in NPS Swasthya, ANPI and HBA shall comply with the provisions of these Guidelines and with the directions issued by the Authority.

39.4. The insurer and TPA shall comply with their participation agreement and common operating protocol to the extent consistent with applicable insurance law and the Insurance Policy.

40. Power to Call for Information

40.1. The Authority may require a PF or any PFRDA-regulated intermediary participating in NPS Swasthya to furnish such information, records, data or documents as it considers necessary.

40.2. The Authority may call for records directly from an HBA in relation to the functions performed by it under NPS Swasthya.

40.3. Where information held by an insurer or TPA is necessary for reconciliation, scheme servicing or subscriber protection, the PF shall obtain and furnish such information to the Authority, subject to applicable law.



41. Power to Issue Directions and Interpretation

41.1. The Authority may issue directions, clarifications or instructions to PFs, PFRDA-regulated intermediaries, ANPI and HBAs for effective implementation of the NPS Swasthya and protection of subscribers' pension interests.

41.2. Any question relating to interpretation of these Guidelines shall be decided by the Authority.